मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 13 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 26 मार्च – 1 अप्रैल 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम...5

हमारा मौन व्यक्तित्व.....7

क्या कहती है हिन्डनबर्ग रिपोर्ट.....8–9

अछूत का सवाल.....11

23 मार्च: भगत सिंह शहादत दिवस

आइये, उनके आदर्शों के लिए काम करने का संकल्प करें

डी. राजा

''सर्वहारा की विजय होगी, पूंजीवाद को हराया जाएगा''–लाल स्कार्फ पहने भगत सिह ने 1930 में लेनिन की पुण्यतिथि पर तीसरे इंटरनेशनल को तार द्वारा भेजे जाने वाले इस संदेश को पढ़ा। भगत सिंह के इस भाव–प्रदर्शन ने न केवल कम्युनिस्ट आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय एकता को रेखांकित किया बल्कि उस महत्वपूर्ण विचारधारा पर भी प्रकाश डाला जिसके अनुसार, वह एक स्वतंत्र भारत और एक संपन्न विश्व का निर्माण करना चाहते थे।

23 मार्च 1931 को भगत और उनके दो साथियों–राजगुरू और सुखदेव–को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर जेल में फांसी लगा दी। पंजाब के गवर्नर को अपनी याचिका में भगत सिंह ने आगे कहा कि, ''जब तक चंद परजीवी भारत के मेहनतकश जनगण और राष्ट्रीय संसाधनों को लूटते रहेंगे, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और बनी रहेगी।'' उन्होंने कहा कि ये शोषक ''हो सकता है शुद्धतः ब्रिटिश पूंजीपति हों या मिश्रित ब्रिटिश एवं भारतीय पूंजीपति हों या फिर शुद्धतः भारतीय पूंजीपति ही हों'' इनके खिलाफ लड़ना चाहिए और उन्हें पराजित किया जाना चाहिए। भगत सिंह समाज को किस तरह समझते थे, उस संदर्भ में हमें अपने समय की वास्तविकताओं पर नजर डालनी चाहिए और उनके बलिदान से सीख लेनी चाहिए।

शहादत दिवस पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते भाकपा महासचिव डी. राजा और अन्य साथी

हाल के दिनों में भारत में असमानता और चंद चुनिंदा हाथों में धर्म–दौलत के संकेंद्रण में अभूतपूर्व पैमाने पर वृद्धि हुई है। आजकल पूंजी के मालिकों का धन–दौलत पैदा करने वालों के तौर पर गुणगान किया जाता है जबकि हाड़तोड़ मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग दो–जून की रोटी और सिर पर एक छत के लिए जूझते रहते हैं। पूंजीपति, संसाधनों और रोजगार को नुकसान पहुंचाकर और बेतहाशा गैर–कानूनी एवं अनैतिक मुनाफाखोरी के जरिये स्वयं ही देश में हर तरफ असुरक्षा पैदा कर रहे हैं।

अडानी ग्रुप का अनैतिक बिजनेस आचरण आज जगजाहिर हो चुका है। सरकार ने इस ग्रुप को हर किस्म के फायदे पहुंचाए, अत्यंत उदारतापूर्वक अनेकानेक परियोजनाएं उसके हवाले की और इस प्रकार राष्ट्रीय रक्षा समेत महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को जोखिम में डालने में योगदान किया। सरकार ने इस ग्रुप की जो जबर्दस्त मदद की और जिस तरह उसका समर्थन किया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर में जो गिरावट आई है और चंद हाथों में धन–दौलत का जो जबर्दस्त संकेंद्रण हुआ है, वह भाजपा सरकार द्वारा नव उदारवाद पूंजीवाद के रास्ते पर चलने का ही एक नतीजा है।

इस नीचतापूर्ण व्यवस्था के संबंध में लेनिन के इस कथन को हमें याद करना चाहिए कि ''जब तक पूंजीवाद रहता है, अधिशेष पूंजी को देश के आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका अर्थ पूंजीपतियों के मुनाफों में गिरावट होगा''।

अब जब कि हम 21वीं सदी पहली चौथाई के अंतिम वर्षों में पहुंच रहे हैं तो मानवता के लिए टिकाऊ भविष्य के साथ पूंजीवाद की सुसंगतता के संबंध में पूरी दुनिया में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। वित्तपूंजी का संकट स्पष्टतया दिखाई पड़ रहा है। हमारे देश में अडानी ग्रुप अपना बाजार मूल्य

शेष पेज 15 पर...

रामलीला मैदान में किसान रैली

लिखित वादे पूरा नहीं करने पर किसानों की मोदी से नाराजगी

रावुला वेंकैया

एमएसपी समेत तमाम मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर देश भर के किसानों ने संसद से महज पांच किलोमीटर दूर दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 मार्च 2023 को हुंकार भरी। मोदी सरकार द्वारा की गई लिखित मांगों को पूरा नहीं किये जाने से नाराज किसानों ने इस महापंचायत में किसानों ने सरकार को और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रावुला वेंकैया ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी वाजिब मांगों के लिए एक और देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। उन्होंने मोदी सरकार को याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र सहित अनेक अन्य संगठनों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के प्रति एकजुटता जाहिर की थी।

किसान सभा के अध्यक्ष ने सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों को लागू करने को स्थगित करने के मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को याद करते हुए कहा कि मोदी सरकार को आखिरकार उन काले कानूनों को संसद में वापस लेना पड़ा। उन्होंने किसानों के बलिदान की सराहना की। आंदोलनकारी किसानों में से साढ़े सात सौ शहीद हो गए थे। 80,000 किसानों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए जो अभी भी अदालतों में लंबित हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसानों द्वारा उनकी जाति, पंथ, धर्म या क्षेत्र के इतर ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था।

अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रावुला वेंकैया ने बिना किसी और देरी के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने और केरल मॉडल फ्रैमरर्स रिलीफ एक्ट को लागू करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने के साथ–साथ किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस ले।

एआईकेएस अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो किसान फिर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने लोगों से कृषि क्षेत्र को कारपोरेट ताकतों को दूर रखने, कृषि क्षेत्र की रक्षा करने और 2024 के अगले आम चुनाव में मोदी सरकार को हराने का आह्वान किया।

एआईकेएस अध्यक्ष रावुला वेंकैया एवं अन्य किसान नेता कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को ज्ञापन देते हुए

विरोध सभा की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता बलदेव सिंह ने की।

जाने माने किसान नेता राकेश

शेष पेज 4 पर...

अभाव के घने अंधेरे में

संपादकीय

भारत आज अभाव के अंधेरे में डूबता जा रहा है जब सबसे गरीब अंतिम बीस प्रतिशत की आमदनी 53 प्रतिशत तक न सिर्फ नीचे आ गई है, बल्कि 2015–16 के स्तर से लगातार नीचे की ओर जा रही है। तीन दशक से भारत सालाना सात प्रतिशत या इससे अधिक की दर से विकास कर रहा था और पैनडेमिक से ठीक पहले भारत की परकैपिटा इनकम 2100 डॉलर प्रतिवर्ष पर पहुंच चुकी थी। यूनाइटेड नेशन डेवेलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार, 2005–06 से 2015–16 तक भारत में 27 करोड़ लोग भयंकर गरीबी से बाहर आ रहे थे। लेकिन 2016–17 से जीडीपी ग्रोथ दर लगातार घटती जा रही है। पैनडेमिक के महीनों मे आर्थिक स्थिति में तेजी से गिरावट आती जा रही थी जो आज भी जारी है। लेकिन महत्व की बात यह है कि घाटे के इन्हीं सालों में सबसे धनी बीस प्रतिशत अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने में काफी कामयाब हुए और 39 प्रतिशत तक की आर्थिक वृद्धि तक पहुंच गए। कोविड के ये दिन समाज में दो धनी और ग़रीब तबकों के बीच गहरी खाई लाने के थे।

पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकॉनोमी ने अप्रैल और अक्टूबर 2021 में 2,00,000 परिवारों में सर्वे करने का निर्णय लिया और पहली पारी में 42,000 परिवारों की सौ जिलों के आठ सौ गांवों से शुरूआत की। आर्थिक सक्रियता इस दौरान घटकर शून्य के स्तर पर आ चुकी थी, विशेषकर 2020–21 के महीनों में और जी.डी.पी. घटकर इस समय 7.3 प्रतिशत पर आ गई थी। इस समय शहरी गरीबों की स्थिति बहुत गिर चुकी थी और पूरे परिवार की आय लगभग बंद हो चुकी थी। इस कटाव के साथ ही एक वर्गीकरण भी शुरू हो चुका था। इस वर्गीकरण में सबसे धनी लोगों की आय आम बाकी वर्गों से काफी ऊंची थी। सबसे भयंकर स्थिति थी सबसे नीचे के 20 प्रतिशत की, जहां 53 प्रतिशत की विशाल कटौती हुई थी। इससे ऊपर के बीस प्रतिशत में, जिन्हें निम्न मध्यम वर्ग कहा जाता है, यह कटौती 32 प्रतिशत तक की थी। मध्यम आय की श्रेणी में यह गिरावट नौ प्रतिशत तक पाई गई जबकि उच्च मध्यम वर्ग में यह सात प्रतिशत तक थी। सबसे धनी बीस प्रतिशत की श्रेणी में उदारीकरण के दिनों से लेकर पैनडेमिक तक सबसे अधिक वृद्धि हुई, और सबसे चिंताजनक बात है कि सबसे गरीब बीस प्रतिशत के लिये तेजी से गिरावट आई और उनका प्रायः सब कुछ छीनते हुए समय बीतता गया, जो आज भी चल रहा है। कोविड के दिनों से ग्यारह साल पहले, उच्चतम धनी बीस प्रतिशत के लिये वृद्धि 34 प्रतिशत थी, और सबसे गरीब के लिये भी औसतन 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2021 में सबसे ग़रीब बीस प्रतिशत के लिये गिरावट 3.3 प्रतिशत पहुंच गई। इसके ठीक विपरीत, सबसे धनी बीस प्रतिशत के लिये, 2021 में यह उछाल 56.3 प्रतिशत तक का था।

पैनडेमिक के बाद अब अर्थव्यवस्था क्रमशः व्यवस्थित होने लगी तो सर्वोच्च बीस प्रतिशत कम आय वाले गरीबों के दम पर अधिक से अधिक कमाने लगे। चोटी के बीस प्रतिशत की श्रेणी को सबसे अधिक लाभ हुआ। सर्वे से यह भी पता चला कि बेरोज़गारी जब लघु और मध्यम उद्योगों को निगलती जा रही थी और अनौपचारिक श्रम (कैजुअल लेबर) से काम चला रही थी, तो बड़ी कंपनियों को इस सबका कोई प्रभाव नहीं झेलना पड़ा। सर्वे से यह भी पता चला कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवर्तनों का असर अलग–अलग ही रहा। सबसे गरीब शहरी बीस प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों के बीस प्रतिशत से अधिक भुगतते रहे। जब दुनिया कोविड और लॉकडाउन से जूझ रही थी। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और रोज़गारों के क्षेत्र में, एक निरंतर बढ़ता हुआ आर्थिक अंकुश फैल रहा था और निम्नतम बीस प्रतिशत के साथ ही अन्य मध्यम भी उसका सामना करने के लिये मज़बूर होते जा रहे थे। इसका सीधा नतीजा था रोज़गार की कमी, आय की कमी, क्योंकि वेतन में भारी कटौती हो रही थी, और इसका भयंकर असर पड़ रहा था अनौपचारिक मेहनतकशों, छोटे व्यापारी और घरों में काम करने वालों पर।

देश की आर्थिक नीति का असर जनता के दुख–दर्द को बढ़ा रहा था, और इन नीतियों के समर्थन से उच्चतम बीस प्रतिशत लाभान्वित हो रहे थे। ग़रीबों और बेरोज़गारों पर ध्यान देने की जरूरत भी देश की व्यवस्था महसूस नहीं कर रही थी।

प्रशासकीय सत्ता ने वित्त पूंजी का साथ देना शुरू कर दिया और ऐसी नीतियों के विनाशकारी प्रभावों से, जो जनता के अधिकतम हिस्से के प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय (परकैपिटा इनकम) में अधिकतम गिरावट लाती है, वे अभी भुगत ही रहे हैं भूख और अपुष्टता से, जिससे बच्चों में प्रतिरोध क्षमता तो कम हो ही रही है, वे पंगु भी हो रहे हैं। वैश्विक भूख स्तर में 166 देशों में भारत का स्थान आज 96वां है, और विमुद्रीकरण या डिमॉनिटाइजेशन ने उन्हें कगार पर धकेल दिया है। करोड़ों लोग आज भयंकर निर्धनता से गुजर रहे है। पैनडेमिक में फैली अव्यवस्था, और गरीबों तथा असहायों के लिये राहत कोष से पैसों की व्यवस्था से इंकार ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया हे।

रोज़गार की संभावनाएं आज 7.2 प्रतिशत ही हैं। शहरी क्षेत्रों में 8.4 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.4 प्रतिशत और इस सबके साथ है भयानक मुद्रास्फीति, उच्च स्तर का अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट कर, जी.एस.टी. के निर्धारण में अव्यवस्था, पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की बिक्री में मुनाफाखोरी, लाइसेंस–परमिट युग की वापसी, पूंजी और धन का केंद्रीकरण, और अंत में इज़ारेदारों या मोनोपॉलीज का सशक्तीकरण बढ़ता ही जा रहा है, और इस सबके साथ ही जनता की नाउम्मीदी भी।

इन संकट के दिनों में जनता अकाल से थोड़े ही कम बदहाली के समय से गुज़र रही है। व्यवस्था जो भी नीतियां अपना रही है, उसकी कीमत जनता को ही चुकानी पड़ रही है।

जल्दी ही वह दिन आयगा, जब व्यवस्था को ये सारा खर्च उठाने के लिये जनता मज़बूर करेगी। क़गार से खाई में गिरना अंतिम सत्य नहीं है, चुनौती का सामना करते हुए नये विश्व का निर्माण अनिवार्य है। यह संधिकाल का आने वाला वादा है।

रोशन कुमार सिन्हा को रिहा करें: भाकपा

पटना, 19 मार्च, 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने अखिल भारतीय नौजवान सभा (एआईवाईएफ) के राज्य सचिव सह राष्ट्रीय सचिव रोशन कुमार सिन्हा की गिरफ्तारी की निन्दा की है। पार्टी राज्य सरकार से मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने की मांग करती है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने बिहार के पुलिस महानिदेशक से कजरा थाना कांड संख्या 99/2022 और किउल रेल थाना कांड संख्या–68/2022 को अपने स्तर से जांच कराने और निर्दोष रोशन कुमार सिन्हा को बरी करने की मांग की है। रोशन कुमार सिन्हा की गिरफ्तारी एक गहरे राजनीतिक षड़यंत्र के तहत हुई है। रोशन कुमार सिन्हा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय और राज्य सचिव हैं। वे लगातार छात्र–युवाओं के सवालों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं। पार्टी नक्सलपंथी राजनीति का विरोधी रही है। नक्सलियों द्वारा कई पार्टी साथियों की हत्या एवं अपहरण की घटनाएं हो चुकी है। अगर वह नक्सली होता तो हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जैसे संगठन का राज्य सचिव नहीं बनाये जाते। यह केवल रोशन कुमार सिन्हा के गिरफ्तार होने का मामला नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से छात्र–नौजवान और आमजनों की आवाज उठाने वाले नेता सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को किस तरह से नक्सली बताकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। पुलिस का यह आरोप भी पूरी तरह गलत है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आन्दोलन में रोशन कुमार सिन्हा ने छात्रों को भड़काया था, जिस वजह से दो ट्रेन को आग के हवाले किया गया था। पुलिस का यह आरोप सरासर गलत और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में छात्र–नौजवानों का अग्निपथ योजना के खिलाफ स्वतःस्फूर्त आन्दोलन हुए। विभिन्न पार्टी एवं छात्र–नौजवान सगठन भी इस योजना के खिलाफ संघर्ष में उतरे थे। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने भी इस योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था। लेकिन राजनीतिक षड़यंत्र के तहत रोशन कुमार सिन्हा को फंसाया जा रहा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुलिस की इस कार्रवाई की निन्दा करती है और रोशन कुमार सिन्हा को रिहा करने की मांग करती है।

भयावाह जातिवादी ताकतों का एक डरावना स्मारक : इंडमतरूति मणा

कानम राजेन्द्रन

वायकम सत्याग्रह संघर्ष, जो 1924 में हुआ था, इतिहास का एक महान प्रतिरोध है जिसका केरल के राजनीतिक और सामाजिक विकास में कोई सानी नहीं है। वायकम सत्याग्रह एक अहिंसक विरोध था। अस्पृश्यता और अनुचित रीति–रिवाज भारत में इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई का विषय कभी नहीं रहे। वायकम सत्याग्रह केरल या पूरे भारत में पहला सफल संघर्ष था जहाँ मेहनतकश लोग हिस्सा ले रहे थे।

कोट्टयम जिले के तालुक वायकम में 1924 में हुआ वायकम सत्याग्रह एक सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई का बिगुल था जिसके समकक्ष केरल के सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास में कोई दूसरी कहानी नहीं है। अहिंसा पर आधारित एक सत्याग्रह, वायकम सत्याग्रह, वह था जिसने पहली बार अस्पृश्यता और अनुचित रीति–रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई, इससे पहले ये मुद्दे भारत में संघर्षो का इतना महत्वपूर्ण का विषय कभी नहीं रहे थे। महिलाओं की अपने स्तनों को ढंकने की आजादी के लिए चन्नार की लड़ाई इस तर्क की पंक्ति में सबसे पहले आई। अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि चन्नार महिलाएँ, जिन्हें निचली जाति की महिलाएँ माना जाता था, को अपनी मर्यादा की रक्षा करने वाले कपड़े पहनने की आजादी हो सकती है। लेकिन, यह पूरी तरह से जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाला नहीं था। 1888 में श्री नारायणगुरु की अरुविपुरम प्रतिष्ठा द्वारा जाति व्यवस्था में विश्वास की नींव को पहले ही चुनौती दी जा चुकी थी, जिसने केरल में सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण रूप से जोश भर दिया थ। विभिन्न संस्कारों के अभ्यास में सुधारों को लागू करके, और शैक्षिक प्रयासों में संलग्न होकर, पुनर्जागरण के नेताओं ने इसका पालन किया।

श्री नारायण गुरु, अय्यंकाली, चट्टाम्बिस्वामी वैकुंठस्वामी, फादर चावरा कुरियाकोस एलियास, पोइकेल योहानन, वेलुकुट्टी अरायन वे थे जिन्होंने केरल समाज को पुनरुद्धार की राह दिखाई थी।

सामाजिक न्याय और मानव समानता को कमतर करने वाले एक जाति–विभाजित समाज के केन्द्र में घोर अन्याय की भावना का प्रभुत्व था।

जाति व्यवस्था की बाधाओं को वंचित वर्ग के एक सदस्य, विद्वान वेलुकुट्टी आर्यन द्वारा नष्ट और समाप्त किया जाना था। केरल में वायकम सत्याग्रह के परिणामस्वरूप जाति आधारित असमानता समाप्त होने लगी। अन्य स्थानों की तुलना में केरल ने ऐसे प्रयासों की विरासत को बनाए रखते हुए सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया।

केरल की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगतिशील वाम तत्व समारा सत्याग्रह आंदोलनों के रोल मॉडल को अपनाकर सामाजिक क्रांति और उत्पीड़ित वर्गों की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे श्रमिकों और किसानों के अधिकारों के संघर्ष का नेतृत्व करने में सक्षम हुए थे। भाकपा सरकार, जो 1957 में इतिहास में दूसरी बार एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चुनी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी के व्यापक समर्थन आधार का एक राजनीतिक परिणाम था। पुनर्जागरण के सभी राजनीतिक मूल्य जो केरल के समाज ने उस बिंदु तक जमा किए थे, राज्य की पहली कम्युनिस्ट सरकार द्वारा उन्हें अपनाया गया, जो केरल के संस्थापक सिद्धांतों की एक अवस्था रूप में कार्य कर रहे थे। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी की संरचना और मूल्यों में आमूल–चूल परिवर्तन किए। यह कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा में भी सुधार लेकर आया। जहां भी इस तरह के कदम उठाए गए, उन्होंने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। लक्ष्यों का निरंतर पालन किया गया।

त्रावणकोर के एझावा मालाबार के थेयर्स से भी बदतर स्थिति में थे। श्रीनारायण गुरु, महाकवि कुमारानाशन और सीवी कुंझीरामन और टीके माधवन जैसे जागरूक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण नागरिक अधिकारों के विमर्श को लोकप्रिय बनाया गया।

वायकम सत्याग्रह में एक और अनसुनी परंपरा श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी और ईवी रामास्वामी नायकर की प्रत्यक्ष भागीदारी थी। 1865 में त्रावणकोर की सार्वजनिक सड़कों को जाति या पंथ की परवाह किए बिना आबादी के सभी वर्गों के लिए साठ साल बाद खोला गया था, हालांकि वायकम महादेवक्षेत्र क्षेत्र अलग बना रहा। जैसा कि अवर्णो को मंदिर की चारों गलियों में आवाजाही की स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, यहां तक कि श्रीनारायण गुरु को भी प्रतिबंध झेलना पड़ा था।

सत्याग्रह को 1923 के काकीनाड़ा सम्मेलन में अधिकृत किया गया था। यह प्रयास टी.के. महादेवन के निर्देशन के तहत किए गए प्रयासों का परिणाम था। माधवन के निर्देशन और संघर्ष ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। 27 सितंबर, 1924 को श्रीनारायण गुरु का आगमन, जिसने प्रदर्शनकारियों में बहुत उत्साह पैदा किया, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गांधी वायकम में मार्च 1925 में आये थे और इंडमतरूति मणा में व्याप्त जाति भेदभाव के बारे में बोले थे। इंडमतरूति मणा के निवासियों में लोकतंत्र की कमी के कारण उनका वायकम के 48 इल्लम में वर्चस्व था। परंपरागत ब्राहमणों का मानना था कि वे भगवान द्वारा बनाये गये कानून की रक्षा कर रहे हैं। वायकम की यात्रा के दौरान गांधी के सामने पहली बार इसे देखने और इसका गवाह बनने का मौका था। इंडमतरूति नंबयात्री ने गांधी जी को कहा कि अछूत इसीलिए अछूत है कि वे उस वर्ण में पैछा हुए हैं और उस वर्ण में अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण पैदा हुए है। इसी कारण से वे अपने किये की सजा पा रहे हैं और भगवान द्वारा ब्राहमणों और राजाओं को उन्हें सजा देने के लिए नियुक्त किया गया है। ब्राह्मणवाद के कर्म सिद्धांत को मानने वाले लोगों के सामने इसका प्रतिवाद प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

गांधीजी को स्वयं ही यह आपत्ति उठानी पड़ी कि अस्पृश्यता हिन्दू सिद्धांत नहीं है। गांधीजी को 'माणा' के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और बहस एक विशेष पंडाल में आयोजित की गई थी जिसे बाहर स्थापित किया गया था। भाजपा का दावा है कि महात्माजी ने स्वयं प्रवेश से इनकार कर दिया क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं थे (भारत के वास्तविक इतिहास और इसके मूल से संघर्ष को फिर से लिखने के लिए संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा) और यह कि गांधीजी ने घर (माणा) का दौरा किया था। उन्होंने हमेशा ऐसा करने का प्रयास किया है। संपत्ति अब कम्युनिस्ट पार्टी के स्वामित्व में है। इस स्थिति की विडंबना जारी है क्योंकि यह अब हमारी पार्टी का कार्यालय है और वे तर्क दे रहे हैं कि इसे एटक और पार्टी से वापस लिया जाना चाहिए। माणा की वर्तमान स्थिति पार्टी और एटक के कब्जे में है, यह इतिहास का बदला है और जातिवादी ताकतों के लिए एक चेतावनी है।

भाजपा का लक्ष्य उन्हीं जाति के अभिजात वर्ग को खुश करना है जिन्होंने ब्राह्मणवादी झंडे का इस्तेमाल किया, आम लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से रोका और अवर्णो को शिक्षा प्राप्त करने से रोका। भाजपा और संघ परिवार की ताकतें ऐसे रवैये अपना रही हैं जो पराजित केरल नवजागरण की परंपराओं और मूल्यों पर नकारात्मक प्रकाश डालते हैं। धार्मिक उग्रवाद और सांप्रदायिक जहर का परिचय देकर भाजपा ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को उखाड़ फेंकने का हर संभव प्रयास किया। इसके अलावा, चरम दक्षिणपंथी सांप्रदायिक समूहों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए प्रशासन द्वारा पूरी तरह से हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालने की खुली छूट दी गई है।

धार्मिक उग्रवाद और सांप्रदायिक जहर लाकर बीजेपी ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को उखाड़ फेंकने की हर संभव कोशिश की. लोगों द्वारा अब तक की गई सभी जीतें– जिनमें आर्थिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, कानून को लागू करना और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली शामिल हैं– खतरे में हैं। संघ परिवार के संगठनों द्वारा हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे इसके व्यापक विरोध की आशा करनी चाहिए। संघ परिवार के संगठनों द्वारा हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे इसके व्यापक विरोध की उम्मीद करनी चाहिए। एक अलोकतांत्रिक फासीवादी दृष्टिकोण के साथ, वे हमारे अद्भुत देश की सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद को मिटाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रकार हमारी साझी संस्कृति भारत की राष्ट्रीय एकता, हमारे लोगों के भाईचारे और मजदूर वर्ग की धर्मनिरपेक्ष एकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह संकट देश के दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुत प्रभावित कर रहा है। वे दुश्मनी को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यकों को पीड़ित करने, जाति और गौ रक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर हत्याएं करने और इसके माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान की नींव है, वह प्रशासन के लिए मूल्यवान नहीं है।

आरएसएस का हिंदुत्व राजनीतिक विचार मनुस्मृति पर आधारित धार्मिक राष्ट्रवाद का एक रूप है। भाजपा का प्रशासन, हिंदुत्व और उसकी एकता को बढ़ावा देता है, और हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देता है, और दलितों और आदिवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। यदि जाति समाज के उन पहलुओं की नींव के रूप में कार्य करती है जो हिंदुत्व की कल्पना करते हैं, तो मनुस्मृति इसकी स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करती है। दलितों, दलित महिलाओं और दलित लड़कियों के खिलाफ हिंसा की भयानक व्यापकता गंभीर नैतिक चिंताओं को जन्म देती है। हिंदू उच्च जाति प्रभुत्व के तहत दलितों के साथ उनका व्यवहार एक गाय की हत्या के लिए उनको फांसी देने का प्रतीक है। सरकार इन स्थितियों में खुले तौर पर उच्च जाति के व्यक्तियों का समर्थन कर रही है जबकि उनका समर्थन करना एक घोर अन्याय है और ऐसा करना हाथरस और कई अन्य जगहों पर असहाय लड़की के खिलाफ किए गए भयावह अपराधों के आरोपो को कमजोर करना है। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जब आरएसएस–भाजपा के नेताओं और विधायकों पर दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया गया है। त्रासदी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और केवल एक संयुक्त मोर्चे के माध्यम से, जो सभी आंदोलनों और धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ बांधता है, सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ लड़ा जा सकता है। इस समय एक धर्मनिरपेक्ष भारत के अस्तित्व को सुनिश्चित करना अनिवार्य है और इसके लिए कोई भी दल अखिल भारतीय आधार पर भाजपा के प्रतिनिधित्व वाली सांप्रदायिकता का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकता है। पूरे विपक्ष को एक ऐसे मोर्चे के रूप में एकजुट होना होगा जो वर्तमान राजनीतिक युग की जिम्मेदारी है। कम्युनिस्ट पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही है।

रामकृष्णा पांडा को मातृ शोक

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सचिव राम कृष्ण पांडा को उनकी मां हेमलता पांडा के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। 17 मार्च की रात करीब 10.35 बजे भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में उनका निधन हो गया।

वे 82 वर्ष की थीं और पिछले 22 दिनों से कैपिटल अस्पताल में भर्ती थीं जिन्होंने एक बडा दिल का दौरा पडने के बाद आखिरी सांस ली। उनके अंतिम समय में रामकृष्ण पांडा के दूसरे भाई राजीव लोचन पांडा और बहने भी सुजाता और माधुरी भी उनके साथ थीं। पार्टी उनके परिवार और राज्य परिषद को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करती है। यह समाचार मिलने के बाद पार्टी महासचिव डी राजा ने रामकृष्ण पांडा और राज्य पार्टी के अन्य नेताओं से बात की और शोक व्यक्त किया।

लिखित वादे पूरा नहीं करने पर किसानों की मोदी से ...

पेज 1 से जारी...

टिकैत, दर्शन पाल सिंह, सत्यवान, आशीष मित्तल, मेधा पाटेकर, वी शोभानदरीश्वर राव आदि ने भी सभा को संबोधित किया।

किसानों और किसान नेताओं में गुस्से और रोष के बीच जहां एक ओर रामलीला मैदान पर किसान महापंचायत चल रही थी, तो दूसरी ओर 15 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कृषि भवन में मुलाकात कर रहा था। इस दौरान किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कृषि मंत्री से मुलाकात से नाखुश किसान नेताओं ने महापंचायत में ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आंदोलन की तैयारी करने का आह्वान किया।

किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने किसानों के बीच अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि कई अनसुलझे मुद्दे हैं और इनके समाधान के लिए और आंदोलन की जरूरत है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। मैं सभी किसान यूनियनों से अपने–अपने राज्यों में रैलियां निकालने और बैठक के लिए पंचायत आयोजित करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा, हम रोजाना आंदोलन नहीं करना

चाहते, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे, जो कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन से बड़ा होगा।

बलदेव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस महापंचायत के माध्यम से हमारा लक्ष्य उन नेताओं को वापस लाना है जो आंदोलन के दौरान कुछ बेपटरी होकर खो गये थे।

किसान नेताओं ने अपने संबोधनों में रेखांकित किया कि बिन मौसम बरसात और बिना गारंटी वादे... हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए जहर से कम नहीं है, और इसी का घूंट पी–पीकर वो देश का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये विडंबना ही है कि जिनके सहारे देश के लोगों का पेट भर रहा है, उन्हें खुद भूखा रहकर दिन–रात सड़कों पर बितानी पड़ती है, ताकि सरकार थोड़ी बहुत उनकी भी सुन ले।

सरकार को किसानों के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिये गये ज्ञापन में किसानों की मांगें निम्न प्रकार हैं:

'स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार, सभी फसलों पर सी2. 50 प्रतिशत के फार्मूला के आधार पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून लाया और लागू किया जाए।

'केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति और इसका घोषित ऐजेंडा किसानों की मांगों के विपरीत है, इसलिए इस समिति को रद्द कर, एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए एमएसपी पर एक नईसमिति को गठित किया जाए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा वादा किया गया था।

'कृषि में बढ़ती लागत और फसल के लिए लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण 80 प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज में डूब चुके हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में सभी किसानों के लिए कर्ज मुक्ति और उर्वरकों सहित लागत कीमतों में कमी की मांग।

'संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ भेजे गए बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए। दरअसल, केंद्र सरकार ने एसकेएम को लिखित आश्वासन दिया था कि मोर्चा के साथ विमर्श के बाद ही विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसे बिना किसी चर्चा के संसद में पेश कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा कृषि के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण परिवारों के लिए 300 यूनिट बिजली की मांग को फिर दोहराता है।

'लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बाहर किया जाए और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

'किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में शहीद और घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करने का वादा जो सरकार ने किया है उसे पूरा किया जाए।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रद्द कर, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, असामयिक या अत्यधिक बारिश, फसल संबंधित बीमारियां, जंगली जानवर, आवारा पशु के कारण किसानों द्वारा लगातार सामना किए जा रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सभी फसलों के लिए सार्वभौमिक, व्यापक और प्रभावी फसल बीमा और मुआवजा पैकेज को लागू करें। नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। 'सभी किसानों और खेत–मजदूरों के लिए हर महीने पांच हजार की किसान पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाए। 'किसान आंदोलन के दौरान भाजपा शासित राज्यों और अन्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी मामले तुरंत वापस लिया जाए। 'सिंघु मोर्चा पर शहीद किसानों के लिए एक स्मारक के निर्माण के लिए भूमि आवंटन किया जाए।

आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश से करीब 32 किसान सगंठनों का जत्था दिल्ली के रामलीला मैदान पर महापंचायत में शामिल हुआ और सभी ने एक सुर में यही कहा कि मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और बड़ा होगा।

अखिल भारतीय किसान सभा का उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन

अखिल भारतीय किसान सभा का 25वां उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन 8–9–10 जून 2023 को गाजीपुर में किया जाएगा। गाजीपुर के लंका मैदान में सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आगामी 2–3 अप्रैल 2023 को 22, कैसर बाग, लखनऊ में किसान सभा की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें किसान सभा के सभी जिलों के मंत्रियों एवं अध्यक्षों के अलावा किसान सभा की राज्य परिषद के सभी सदस्य भाग लेंगे।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

सेवानिवृत्त फौजियों के ''वन रैंक वन पेंशन'' के अंतर्गत बकाया पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं सरकार के पास

यूं तो केंद्र सरकार अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने का दावा करती रहती है परंतु सेवानिवृत्त फौजियों के ''वन रैंक वन पेंशन'' के अंतर्गत बकाया पेंशन का भुगतान करने के लिए उसके पास पैसे नहीं। सेवानिवृत्त फौजियों के प्रति सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उन्हें ''वन रैंक वन पेंशन'' के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 15 मार्च 2023 तक सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनधारियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय, रक्षा मंत्रालय ने पेंशन के बकाया को चार छमाही किस्तों में भुगतान करने के लिए 27 फरवरी 2023 को एक पत्र जारी कर दिया। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के मामले में कानून अपने हाथ में लेने के खिलाफ रक्षा मंत्रालय को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा–रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। रक्षा सचिव ने अधिसूचना जारी की है, वह सीधे तौर पर आदेश के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को इस संबंध में नोट देने के लिए कहा कि क्या किया गया है, क्या किया जाना बाकी है, टाईम शेड्यूल क्या है, कब तक भुगतान किया जाएगा और उसके क्या तौर–तरीके होंगे।

20 मार्च को इस संबंध में जब सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की तरफ से पेश अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफा पेश किया। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने आश्चर्य जताया कि यहां गोपनीयता क्या हो सकती है, क्योंकि मामला अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वेंकटरमानी से कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हूं। इसमें क्या होता है, हम जो कुछ देखते हैं, वह नहीं होता। हम उसे दिखाए बिना मामले का फैसला करते हैं। **यह मूल रूप से न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है।** अदालत में गोपनीयता नहीं हो सकती। न्यायालय को पारदर्शी होना चाहिए। केस डायरी में गोपनीयता समझ में आती है.....अभियुक्त इसका हकदार नहीं है, या कुछ ऐसा जो सूचना के स्रोत को प्रभावित करता हो या किसी के जीवन को प्रभावित करता हो। लेकिन यह पेंशन के भुगतान करने का हमारा फैसला है। अटार्नी जनरल ने हालांकि कहा कि कुछ संवेदनशीलता के मुद्दे हैं, अदालत ने सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। तब अटार्नी जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से एक आवेदन दिया जिसमें बकाये के भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

एक बार में भुगतान करने में केंद्र सरकार द्वारा बताई गई वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार ''वन रैंक वन पेंशन'' के तहत पूर्व सैन्यकर्मियों को बकाया राशि का भुगतान करने पर उसके 2022 के आदेश का पालन करने की लिए बाध्य है और उसने केंद्र से 2019–2022 के लिए उन्हें अगले साल 28 फरवरी तक 28,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि देने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया:

– 70 साल और उससे अधिक उम्र के पूर्व सैन्यकर्मियों (जिनकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख है) को सरकार या तो 30 जून 2023 से पहले एक किस्त में भुगतान करे अथवा एक या ज्यादा किस्त में 30 जून से पहले पूरा भुगतान करे।

– शेष रहे 10 से 11 लाख तक पेंशनरों को तीन किस्तों में–31 सितंबर 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक–पूरा बकाया भुगतान किया जाए।

– 6 लाख फैमली पेंशन और वीरता पदकधारकों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया भुगतान किया जाए।

सीलबंद लिफाफे में सरकार ने क्या लिखा था, कोई नहीं जानता। परंतु इस घटनाक्रम से यह समझने में कोई देर नहीं लगती कि सरकार ने रोना रोया होगा कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, बकाया राशि का भुगतान कर सके। बहरहाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा लेने से इंकार कर दिया तो सरकार ने भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की गुहार लगाई।

अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ''वन रैंक वन पेंशन'' योजना के तहत बकाया पेंशन के भुगतान के लिए जब रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से बजट की मांग की तो जवाब मिला कि उसके पास फंड नहीं है।

तो यह है केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति की वास्तविक हालत!

बंद लिफाफे का तरीका निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के विपरीत

अब से पहले कई मामले ऐसे हो चुके है कि जब सरकार के पास अपने पक्ष और तर्क को उचित ठहराने का कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने सीलबंद लिफाफे पेश कर अदालत में अपनी खाल बचाने की तरकीब अपनाई। ऐसा राफेल मामले में हो चुका है। अभी हाल में हिन्डनबर्ग–अडानी मामले में सेबी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में नामों का प्रस्ताव किया गया था जिसे लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

राफेल के मामले में भी सरकार ने विरोधियों के दावे को मात देने के लिए सीलबंद लिफाफे में नोट देने का तरीका अपनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। और राफेल घोटाले की जांच की मांग अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई।

''वन रैंक वन पेंशन'' के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि बंद लिफाफे का तरीका निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के विपरीत है, एक महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम है।

आरएसएस का एक कुटिल पैंतरा

14 मार्च 2023 को आरएसएस का एक कुटिलतापूर्ण बयान आया है। आरएसएस के सरकार्यवाहक (महासचिव) दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत पहले से ही एक ''हिन्दू राष्ट्र'' है।

इस कुटिलतापूर्ण बात का मानो औचित्य ठहराने के लिए उन्होंने कहा कि ''हिन्दू राष्ट्र'' एक सांस्कृतिक अवधारणा है और इसे संविधान द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बयान की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राज्य दो अलग–अलग चीजें है। जहां राष्ट्र एक ''सांस्कृतिक अवधारणा'' है, वहीं राज्य वह है जिसे संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही एक हिन्दू राष्ट्र है।

इसी प्रकार भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 21 मार्च को इंदौर में कहा कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने और देश के विभाजन के बाद भारत का जो हिस्सा बचा वह ''हिन्दू राष्ट्र'' था। उन्होंने कहा, ''जब भारत का विभाजन हुआ था वह इस मुद्दे (धार्मिक आधार) पर हुआ था। पाकिस्तान बना और बाकी भारत हिन्दू राष्ट्र है''।

निश्चय ही, आरएसएस और भाजपा के इन नेताओं के ऐसे कथन भारत के संविधान के विरूद्ध हैं। भारत के संविधान में सुस्पष्ट तरीके से कहा गया है कि ''भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक'' गणराज्य है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भारत को ''हिन्दू राष्ट्र'' बताए।

आरएसएस और भाजपा के इन नेताओं को भारत के इतिहास की भी सही जानकारी नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था।

ऐसा भी नहीं है कि ये लोग इन बातों को नहीं जानते। परंतु आरएसएस और भाजपा का एजेंड़ा है कि भारत को ''हिन्दू राष्ट्र'' घोषित किया जाए। जब से केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा/आरएसएस सरकार सत्ता में आई है, आरएसएस के संरक्षण में विभिन्न सांप्रदायिक तत्वों ने ''हिन्दू राष्ट्र'' के एजेडे को बड़े पैमाने पर उछालना शुरू कर दिया है। यहां तक कि तथाकथित अनेक ''धर्म संसदों'' के जरिये इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाने की कुत्सित योजनाएं चलाई जा रही हैं।

युवाओं में बेरोजगारी का हाल

यूं तो भारत में जब बेरोजगारी की बात की जाती है तो बताया जाता है कि 7–8 प्रतिशत के आसपास बेरोजगारी चल रही है। परंतु बेरोजगारी का यह प्रतिशत भारत में बेरोजगारी की, खास तौर पर युवाओं में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति का बयान नहीं करती। वास्तविक स्थिति यह है कि स्कूलों/कालेजों/ विश्वविद्यालयों से हर साल निकलने वाले अधिकांश छात्र बेरोजगार हैं। शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकलने के बाद उन्हें वर्षों तक रोजगार नहीं मिलता; उनमें से बड़ी संख्या में युवाओं को तो कभी भी रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसी हालत में ,उनका परिवार या परिवार का कोई सदस्य जो छोटा–मोटा काम करता है या खेती आदि का काम करता है, ये बेरोजगार युवा उसी में थोड़ा–बहुत हाथ बंटाने लगते है और सरकारी आंकड़ों में इनकी गिनती बेरोजगारों में नहीं की जाती।

इस प्रकार बेरोजगारी के संबंध में जो आंकड़े आते हैं वे वास्तविक स्थिति का सही बयान नहीं कर करते।

नेशनल सैम्पल सर्वे आफिस (एनएसएसओ) की इसी महीने जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे 15 से 29 साल के 32.9 प्रतिशत युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न कोई काम–धंधा कर रहे हैं, और न किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं।

एनएसएसओ ने सभी राज्यों के कुल 2.9 लाख परिवारों पर जनवरी 2020 से अगस्त 2021 के बीच यह सर्वे किया। खाली बैठे युवाओं में से 20.3 प्रतिशत तो काम की तलाश भी नहीं कर रहे। यह नहीं कह सकते कि 20.3 प्रतिशत युवा काम नहीं करना चाहते। यदि वे काम की तलाश नहीं कर रहे हैं तो सम्यक जांच करने पर इसके अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि ये लोग रोजगार की तलाश करते–करते थक गए हैं और इतने निराश हो चुके है कि उन्होंने रोजगार की तलाश करना भी छोड़ दिया है।

इस सर्वे के अनुसार, 15–29 आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश के 36.7 प्रतिशत, बिहार के 36.5 प्रतिशत, पंजाब के 36.5 प्रतिशत, गुजरात के 33.9 प्रतिशत, हरियाणा के 33.4 प्रतिशत, मध्यप्रदेश के 32.4 प्रतिशत, झारखंड के 28.2 प्रतिशत, राजस्थान के 27.8 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ के 26.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र 25.3 प्रतिशत युवा ऐसे हैं जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न कोई काम–धंधा कर रहे हैं, और न किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। भले ही सरकारी आंकड़ों में इन्हें बेरोजगार न माना जाए, पर यह एक हकीकत है कि ये लोग बेरोजगार हैं।

सर्वे के अनुसार, भारत में 15 से 29 आयु वर्ग के 38 करोड़ युवाओं में से हर तीसरा युवा ऐसा है जो न तो पढ़ाई कर रहा है, न कोई काम–धंधा कर रहा है, और न किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है। क्या इसे ही विकास कहते हैं कि देश के एक–तिहाई नौजवान बेरोजगार हैं?

रेलवे को बर्बाद किया मोदी सरकार

अकसर सरकार दावा करती रहती है कि उसने ''वंदे मातरम्'' नाम जैसी गाड़ियां चलाकर रेलवे को चार चाँद लगा दिए हैं। परंतु असलियत यह है कि मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद कर दिया है। हालत यह हो गई है कि 2021–22 वर्ष में रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 107.39 रुपए खर्च कर रही थी। कोई संस्थान यदि 100 रुपए कमाने के लिए 107.39 रुपए खर्च करे, तो क्या उसका अर्थ यह नहीं है कि वह संस्थान बर्बादी के कगार पर ही नहीं पहुंच रहा है बल्कि बर्बाद हो चुका है?

रेलवे की ऐसी दुर्दशा आजादी के बाद कभी नहीं हुई। मोदी सरकार को

शेष पेज 12 पर...

कर्नाटक में प्रत्येक बेघर को मिले आवास : भाकपा

भाकपा कर्नाटक राज्य परिषद ने मुफ्त आवास और राज्य में बेघरों के लिए जमीन की मांग को लेकर एक पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा ''सूरीगागी कोटी हेज्जे'' के नाम से निकाली गई थी।

हालांकि यह पदयात्रा 2 फरवरी 2020 को बेल्लारी से पार्टी राज्य परिषद सचिव साथी सुंदरेश के नेतृत्व में निकाली गई थी लेकिन कोविड महामारी (तालाबंदी) के कारण पदयात्रा को बीच में ही स्थागित करना पड़ा। इस पदयात्रा को 26 फरवरी 2023 को तुमकुर से ही शुरू किया गया चूंकि पिछली बार चली पदयात्रा को तुमकुर में ही स्थागित किया गया था। तुमकुर से चली यह पदायात्रा 9 मार्च 2023 को बंगलुरू पहुंची। पदयात्रा के बंगलुरू पहुंचने के बाद जन सभा की गई। होमलेस लैंडलेस कमेटी (बेघर बेजमीन कमेटी) के अध्यक्ष एम.सी. डोगरे ने जनसभा की अध्यक्षता की। पार्टी राज्य परिषद के सहायक सचिव बी. अमजद ने पदयात्रियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में हजारों साथियों ने भाग लिया।

पार्टी राष्ट्रीय परिषद सचिव और पार्टी संसदीय दल के नेता बिनोय विश्वम ने इस जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में बिनोय विश्वम ने कहा कि, 'भाकपा जनगण की मुख्य जरूरतों को उठा रही है। केवल हमारी पार्टी ही निःस्वार्थ रूप से जनगण के कल्याण के लिए काम कर सकती है। भाकपा ने कर्नाटक में सभी विपक्षी दलों का आह्वान किया था कि आगामी कर्नाटक राज्य विधान सभा में सांप्रदायिक और भ्रष्ट भाजपा को हटाने के लिए एकजुट हों। यहां तक कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक पत्र भी भेजा था। लेकिन कांग्रेस ने पत्र का सकारात्मक जवाब नहीं दिया। विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर हमें संदेह है। कांग्रेस को सीखना चाहिए डीएमके से कि कैसे भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी ताकतों के लिए जगह बनाई जाए।''

कर्नाटक पार्टी राज्य परिषद सचिव साथी सुंदरेश ने अपने संबोधन में कहा कि:

''पदयात्रा के दौरान कई गांवों में पार्टी नेताओं ने दौरा किया। हमारे जत्थे का समाज के सभी लोगों ने स्वागत किया। जत्थे की पूरी यात्रा के दौरान कई बेघरों और भूमिहीनों ने मकान के लिए प्रार्थना पत्र दिए। जत्थे ने एक हजार किलोमीटर की यात्रा के दौरान लाखों लोगों से संपर्क किया। इस बार मुख्य चुनावी मांग सभी के लिए आवास की होगी। भाकपा तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक राज्य में सभी को आवास नहीं मिल जाता।

होसातु मासिक पत्रिका के संपादक ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. सिद्धनगौड़ा पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि, ''भाकपा घर की मांग कर रही है। लेकिन भाजपा नीत राज्य सरकार भ्रष्ट कामों में लगी है। भाजपा विधायक मादल विरूपक्ष भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी हैं। उसके घर से करोड़ों रु. मिले थे। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद बाहर आकर उन्होंने एक रैली निकाली जिसमें भाजपा के झंडे लहरा रहे थे। भाजपा के झंडे भ्रष्टाचारी लोगों को बचा रहे हैं।

मोदी ने 2014 में कई अन्य वादों के अलावा सभी के लिए घर का वादा भी किया था, लेकिन मोदी अपना वादा पूरा करने में विफल रहे।''

जनसभा में पी.वी. लोकेश पूर्व पार्टी राज्य परिषद सचिव, विजय भास्कर राष्ट्रीय परिषद सदस्य शिवराज बिरादर, जर्नादन, ज्योति ए., सत्यानंद, संतोष एच.एम. पार्टी राज्य परिषद सचिव, नागभूषण राव राज्य कंट्रोल कमीशन सदस्य, पार्टी जिला परिषद सचिव और जन संगठन नेताओं ने हिस्सा लिया।

भाकपा केरल राज्य परिषद सचिव कानम राजेन्द्रन, भाकपा तमिलनाडु राज्य परिषद सचिव एम. मुथुरासन, तेलंगाना राज्य परिषद सचिव कुनामेनी संबाशिव राव और आंध्रप्रदेश राज्य परिषद सचिव के रामकृष्णा ने पदयात्रा कार्यक्रम के लिए विशेष संदेश भेजे। जनसभा के दौरान इन संदेशों को भी पढ़ा गया।

साथी सुंदरेश के नेतृत्व में एक पार्टी प्रतिनिधिमंडल आवास मंत्री और राजस्व मंत्री से मिला और इस संबंध में एक ज्ञापन उन्हें सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया था कि:

राज्य की कुल आबादी का लगभग 46.57 प्रतिशत हिस्सा भूमिहीन हैं। कर्नाटक में जब बी.एस. येदुरुप्पा मुख्यमंत्री थे तब उस समय आवासीय विभाग द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार, राज्य में लगभग 37 लाख परिवार बिना आवास और भूमि अधिकार के थे। राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन के पास 16 लाख आवेदकों के आवास के लिए निवेदन पत्र हैं, अनुमान लगाया गया है कि कर्नाटक में लगभग 50 लाख बेघर परिवार हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि आवास और भूमिहीनों के संबंध में एक वैज्ञानिक ढंग से सर्वे कराए। यह शर्म की बात है कि ये परिवार आवास की समस्या से उभरने के लिए लड़ रहे हैं। वे शहरों में ऊंचे दामों पर घर किराये पर लेते है या शहरों में बेघर रहते हैं। बिना किसी आश्रय के उन्हें हमारे राज्य में घुमंतु

हरीश बाला

घर की मांग के लिए जारी रहेगा संघर्ष

का जीवन बिताना पड़ता है।

राज्य सरकारों ने कागजों पर ग्राँड हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं पर इन योजनाओं ने इन परिवारों के आवास अधिकारों में सुधार के लिए मुश्किल से कोई प्रभाव डाला है। सरकार की विभिन्न हाउसिंग स्कीमों के लाभार्थी उन्हें मुहैया कराए गए धन से घर बनाने के काम को पूरा नहीं करवा सके हैं और पूरे राज्य में इस तरह आधे–निर्मित घर इस तथ्य के मूक गवाह हैं। वास्तव में इस तरह की दोषपूर्ण स्कीमों और इनके क्रियान्वयन से कई गरीब परिवार कर्ज और मनमाने ब्याज के जाल में फंस गए हैं।

कर्नाटक राज्य के सामाजिक–आर्थिक सर्वे का कहना है कि कई आवासीय योजनाओं की असफलता का सबसे बड़ा कारण जमीन की अनुपलब्धता है, इस तथ्य को सभी ने माना है। ग्राम पंचायत के पास सरकारी जमीन न होने के कारण राज्य (स्थानीय) सरकार के लिए घर उपलब्ध करवाना असंभव है। इन परिस्थितियों में, कर्नाटक में बेघरों की संख्या रोज बढ़ रही है। राज्य सरकार की भू–पुनर्वितरण पर स्पष्ट नीति के न होने के कारण इस समस्या की जटिलता समाज में केवल बखेड़ा और तनाव पैदा करेगी और आवास का अभाव साथ ही मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है।

सरकार ने राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन को उपयुक्त हाउसिंग नीति बनाने का प्राधिकार सौंपा है। कारपोरेशन आवास आवंटन में विकलांगों, एड्स पीड़ितों, रेहड़ी–पटरी–फेरीवालों, भारी बोझ ढोने वाले मजदूरों, बीड़ी वर्करों, देवदासियों, एकल महिलाओं, बाढ़ में घर और जमीन खोने वाले, तालाबों के निर्माण और वनिकी से आवास खोने वालों, आंगनवाड़ी वर्करों, सेक्स वर्करों, सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए मजदूरों, और घुमंतु लोगों को प्राथमिकता देती है। तो भी, कारपोरेशन वरियता सूची में ट्रांसजेंडर समुदाय का नाम नहीं है। अतः स्कीम के लिए यह जरूरी है कि वह समावेशी हो और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को इसमें शामिल करें।

यह भी समझना जरूरी है कि राज्य में आवासीय समस्या के कई प्रांतीय रूपांतर हैं, जिसका अर्थ है कि इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व विभाग को विाभिन्न क्षेत्रों से आवास की मांगों को ध्यान में रखते हुए पांच लाख एकड़ जमीन आरक्षित करनी होगी।

राज्य में दो करोड़ जनता के आवास अधिकारों और इस समस्या की व्यापकता के प्रचार के लिए भाकपा राज्य परिषद और बेघर और भूमिहीन कमेटी ने मिलकर पैदल चलकर हजार किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली, यह यात्रा 62 दिनों में पूरी होगी।

9 मार्च 2023 को आवास अधिकारों के विरोध प्रदर्शन स्थल फ्रीडम पार्क से आवास अधिकारों की मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से निम्न मांग की:

– आवास के लिए जमा किए गए आवेदनों के साथ एक नए आवेदन पर आधारित आवास की जरूरतों का ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे किया जाना चाहिए।

– सर्वे में चिन्हित की गई जरूरतों के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीन का उपयुक्त तौर पर आवास के लिए आरक्षित करना चाहिए।

– लाभार्थियों को इस तरह की जमीन का अधिकारी घोषित करने के साथ ही उन्हें उक्त जमीनें भी आवंटित करनी चाहिए।

– सरकार को अनुमोदित आवास योजनाओं के कोष को तुरंत मुहैया कराना चाहिए।

– सरकार को समुचित आवास के लिए व्यैक्तिक हाउसिंग प्लान की जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाकर एक हजार वर्गफीट करना चाहिए।

– सरकार को आवासीय योजना का लाभ दायरा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की सालाना आय वालों को इसमें शामिल करना चाहिए।

– शहरी क्षेत्रों में जहां जमीनें उपलब्ध नहीं हैं, वहां दो कमरे वाले बहुमंजिला भवनों का निर्माण करना चाहिए।

–सरकार को अविलंब ऑनलाइन आवेदनों के लिए मंजूरी देनी चाहिए, सरकार ने इन ऑनलाइन आवेदनों पर रोक लगाई हुई है।

– सरकार को आवास स्कीम की वरियता सूची में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का नाम लिखना चाहिए।

– सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय सरकार भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्करों को तत्काल कोलार में आवास का अधिकार मुहैया कराए।

– कुंद्रेमुख के दिहाड़ी मजदूरों के लिए आरक्षित जमीन को तत्काल वितरित करनी चाहिए।

भाकपा ने 50 लाख बेघर और भूमिहीन परिवारों की आवास की मूलभूत मांग के लिए यह ऐतिहासिक मार्च संघटित किया है।

शुद्धिपत्र

अंक 12 (19–25 मार्च 2023) के पेज 16 पर गुरनाम कंवर की रिपोर्ट के शीर्षक में त्रुटी है। रिपोर्ट का सही शीर्षक है: 'फासीवादी विरोधी मोर्चे की विशाल रैली'।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दर:

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नाम: **मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक**
बैंक: **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्या: **1033004704**
आईएफसी कोड: **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखें:
व्यवस्थापक: मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोट: डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

हमारा मौन व्यक्तित्व

ए आर वासवी

हाल ही में, मैंने गुजरात दंगों के 21वें साल पर पर जले हुए गुलबर्ग सोसाइटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को देखने गई जाकिया जाफरी की तस्वीरें देखीं। जाकिया जाफरी के आचरण ने जिस तरह से उन पर लगाई गई सभी तरह की हिंसाओं, अपमान और विश्वासघात को उजागर किया है इस बात ने मुझे प्रभावित किया। दंगों के दो दशकों के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की सत्ता और शक्ति में वृद्धि हुई है, और हम सभी समाज और राष्ट्र के सदस्यों के रूप में बहुत हद तक इस विडंबना के मूक गवाह बने हुए हैं जो कि इशारा करता है कि हम कैसे मौनधारी बन गए हैं।

जैसा कि लोकतांत्रिक ढांचे और मानदंड कमजोर हुए हैं, इस सामूहिक हानि की स्वीकृति और सामूहिक हानि के प्रति उदासीनता बढ़ती सी लग रही है। एक विचित्र तरह की उदासीनता हमारे समाज के मध्यम और उच्च वर्गीय दायरों की पहचान बन गई है। बातचीत में कई दूसरे तरह के सामाजिक अवमूल्यन और लोकतांत्रिक अभाव के मामलों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इसके समाधान के लिए क्या कर सकता है।

स्वतंत्रता के 75 वर्षों में, अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा, काम के अवसरों और स्थायी कैरियर से जिस वर्ग ने बढ़ोतरी की है वह शहरी उच्च मध्य वर्ग है। भारत के लोकतंत्र ने, 1950 के मध्य दशक से लेकर 1970 तक, शहरी मध्य और उच्च वर्ग के परिवारों में पैदा हुए लोगों के लिए कई अवसर प्रदान किए, अक्सर दूसरे अन्य लोगों को इस तरह के अवसरों से वंचित करते हुए। तब भी, अब जब देश के सार्वजनिक संस्थानों में और संस्कृति में हिन्दू राष्ट्रवाद और अधिक कड़कड़ाते हुए बहुसंख्यकवाद, सांस्कृतिक एकरूपता, विशिष्टतावाद के लिए आह्वान कर रहा है ऐसे में उन सभी लोगों की आवाज और कर्त्ता बोध लापता है, जिन्होंने लोकतांत्रिक संस्कृति से सबसे अधिक लाभ उठाया है। हिंसा की प्रत्येक सार्वजनिक घटना, प्रत्येक कृत्य जो लोकतंत्र के नियमों का उल्लंघन और अवहेलना करते हैं अक्सर समाज में बगैर विरोध के गायब हो जाते हैं, बहुत हुआ तो ऑनलाइन याचिकाओं की हलचल होती है और इन घटनाओ पर होने वाले विरोध बड़े पैमाने पर संघटित और सतत नहीं होते हैं। देश भर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों ने लोकतंत्र को फिर से हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की संभावनाएं रखी थी, लेकिन कोविड और दिल्ली में हुए दंगों ने उन्हें नाकाम कर दिया। तब से, शहरी, उच्च वर्गों के बीच एक गहरा समर्पण सा लगता है। लोकतंत्र पर फिर से दावे के लिए बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शनों में कम संख्या में लोग होते हैं उनमें भी ज्यादातर 20 से 30 की उम्र के और कुछ एक लोग 60 के आसपास की उम्र के पुराने प्रगतिशील लोग होते हैं, इन प्रदर्शनों में जिस उम्र के लोगों का सहयोग नदारद रहता है वे हैं 40 से 60 साल की बीच वाली उम्र के लोग।

कोई केवल यह कयास लगा सकता है कि इस उम्र समूह के, जो कि एक जनतान्त्रिक प्रणाली से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ और जो उम्र समूह जनतंत्र के झंडाबरदार के जैसे जाना जाता है, की चुप्पी और विरोध प्रदर्शनों से अनुपस्थिति के कारण क्या हैं। छठे और सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतन देने के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन को निजी क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्धी बना दिया। इन वेतनमानों ने एक ऐसी आकांक्षापूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया जिसमें उपभोक्तावाद उस अर्थव्यवस्था की एक पहचान बन गया है। जीवन शैली की मांगों में उलझा होने के कारण, मध्यम और उच्च वर्ग सर्वजन सरोकारों के लिए समय नहीं दे सकता, यहां तक कि उन मुद्दों के लिए भी जो कि उसके अपने रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के एक लेक्चरार ने मुझे बताया कि फैकल्टी (लेक्चरार, प्रोफेसर आदि) अब सार्वजनिक चिंता के मुद्दों की तुलना में अपने बच्चों के लिए नवीनतम कारों, आवास योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति में अधिक रुचि रखते हैं।

इस तरह की बढ़ती उदासीनता इस तथ्य को बताती है कि हाथरस के पीड़ित के लिए या बिलकिस बानो के साथ हुए अन्याय के लिए आक्रोश और गुस्सा दिसंबर 2012 के दिल्ली के बलात्कार मामले के जैसा नहीं था। प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं पर निर्मम कार्रवाइयों, खासतौर से एल्गर परिषद मामले में, को डराने और असहाय बनाने के निमित्त लगाया गया है और इसलिए यह उस मध्य वर्गीय समूह के पीछे हटने का कारण है। फिर भी, बातचीत से पता चलता है कि वे मुद्दों के बारे में विस्तार से जानने में असफल हैं, विशिष्ट तरीकों से समर्थन देने में असमर्थ हैं और मुद्दों के पक्ष में खड़े होने में हिचकिचाते हैं।

एक युवा व्यक्ति ने अपने उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ने के बाद विस्तार से बताया कि कैसे लोकतंत्र और मानवतावाद के बुनियादी मानदंडों की तुलना में करियर के हितों को प्राथमिकता देने से कई लोगों को व्यवस्था ने अपने में मिला लिया है । यहां तक कि उच्च संपत्ति वाले व्यक्ति अन्य देशों की नागरिकता या घर खरीदने की कोशिश में देश छोड़ रहे हैं। उच्च मध्यम वर्ग यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि उनके बच्चे कहीं और अपना जीवन बना सकें। तब लोकतंत्र के लिए प्रयास एक दूर की चिंता बन जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक उभरते हुए शेयर बाजार के आश्वासन से और कई लोगों की बगैर रोजगार के कमाई करने की क्षमता से चुप्पी और आत्मसंतोष को खरीद लिया गया है।

तब भी इस तरह की आर्थिक आजादी ने लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने में सक्षम नहीं बनाया लेकिन सरकार की सभी असफलताओं को भूलने का मापक बन गया।

'एक्टिविस्ट' जैसे लेबल का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक मुद्दों में शामिल होते हैं या उनमें योगदान करने की कोशिश करते हैं और समाज में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों से दूरी बनाई जाती है। यहाँ तक कि जब हमारा समाज और देश एक ऐसे भविष्य की ओर झोंका खा रहा है जिसमें कि लोकतंत्र और शालीनता के हल्के से आभास की अवहेलना की जाती है, तब हम आधारिक संरचना में लगतार समर्थकों की कटौती देख रहे हैं, समर्थक जो कि इन अपरिहार्य मानकों की जरूरत के लिए दावा और संघर्ष कर सकते हैं।

आजादी के 75 साल बाद अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हममें से कुछ ने जो भी आजादी के आनंद उठाए हैं उनमें से कितने उस समय उपलब्ध होंगे जब देश 2047 में "आजादी" की स्वर्ण जयंती मना रहा होगा। 'मैं क्यों एक मौन दर्शक नहीं हूँ' नाम की संक्षिप्त आत्मकथा में फादर स्टेन स्वामी, यूएपीए जैसे कठोर कानून के सबसे बहादुर पीड़ित, ने लिखा कि हमारा समय वह समय है जब "सच इतना कड़वा बन गया है, असहमति इतनी असहनीय हो गई है और न्याय पहुँच से इतना बाहर हो गया है"। इस तरह की अनिष्ठसूचक प्रवृतियों के बावजूद भी क्या हम मौन स्वत्व धारण रखना जारी रखेंगे यह हमारे ऊपर और हमरी चेतना पर है।

(साभारः इंडियन एक्सप्रेस)

भाकपा दिल्ली राज्य परिषद की बैठक हुई

नई दिल्लीः भाकपा दिल्ली राज्य परिषद की बैठक के. नारायण, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली राज्य प्रभारी की उपस्थिति में राज्य कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता शंकरलाल, सदस्य सचिवमंडल भाकपा दिल्ली प्रदेश व राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने की।

दिल्ली में 14 अप्रैल से 15 मई तक चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, पार्टी के विस्तार और जनमोर्चो के लिए भाकपा राष्ट्रीय परिषद के फैसलों के मद्देनजर बैठक में निर्णय लिए गए।

भाकपा नेता के. नारायण ने पुडुचेरी पार्टी नेशनल काउंसिल की बैठक में राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर अपनाए गए दस्तावेज की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध वास्तव में अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में रूस और नाटो के बीच युद्ध है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ अमेरिकी साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता था। यहां तक कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि अगर नाटो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दे तो युद्ध तुरंत रुक सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी, मोदी सरकार नहीं चाहती कि अडानी–हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जेपीसी हो। यह दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। सभी विरोधी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तत्काल जेपीसी का गठन किया जाए।

के. नारायणा ने पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से बताया। एक स्वयंभू खालिस्तानी कमांडर अमृतपाल सिंह ने न केवल थाने पर हमले का नेतृत्व किया बल्कि दो बार पुलिस को डराते हुए फरार हो गया। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह कई राज्य और केंद्रीय पुलिस से भाग सकता है, जबकि उसके साथ अन्य को गिरफ्तार किया जाता है। इस थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल है. यहां तक कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी यही कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ लोगों से अप्रत्यक्ष मौन समर्थन प्राप्त है। केंद्र सरकार भारत के लोगों के साथ अडानी धोखाधड़ी के लिए लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।

अंत में प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सचिव सीपीआई दिल्ली राज्य और राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने दिल्ली की राजनीति और संगठन की रिपोर्ट को आगे जोड़ा साथ ही उन्होंने बैठक के दौरान 15 राज्य परिषद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दिया।

क्या कहती है हिन्डनबर्ग रिपोर्ट...

पिछले अंक से जारी....

56. मिल्यिकत के संबंध में जो नए रिकॉर्ड सामने आए हैं वे दिखाते हैं कि पीएमसी प्रोजेक्ट्स का मालिक चांग चुंग लिंग का बेटा है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, चांग चुंग लिंग विनोद अडानी का नजदीकी सहयोगी है। ताइवान के मीडिया में रिपोर्ट है कि चांग चुंग लिंग का बेटा ''अडानी ग्रुप का ताइवान–प्रतिनिधि'' है। हमें ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें वह आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम में, जहां वह अडानी. का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अडानी नामपट्ट को लिए हुए है। एक बार फिर यह सवाल है कि जैसा कि सरकार ने पहले आरोप लगाया था, क्या पीएमसी प्रोजेक्ट्स अडानी के लिए महज एक ''डमी फर्म'' है?

57. यदि ऐसा है, दोनों में से कोई–सी भी कंपनी ने अपनी बड़े पैमाने पर हुई डीलिंगों में रिलेटिड पार्टी ट्रांजेक्शन होने के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जो कि जरूरी था?

58. वित्तवर्ष 20 में ''आदिकोर्प एंटरप्राइजिज ने मात्र 6.9 मिलियन रुपए (97,000 अमरीकी डॉलर) का शुद्ध मुनाफा कमाया। ठीक उसी वर्ष, अडानी ग्रुप की चार कंपनियों ने उसे 87.4 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण दिया। इन ऋणों में कोई वित्तीय विवेक मुश्किल से ही नजर आता है। इन ऋणों को लेते समय क्या अंडर राइटिंग प्रक्रिया एवं क्या बिजनेस औचित्य था?

59. आदिकोर्प ने लगभग तत्काल ही इन ऋणों के 98 प्रतिशत को सूचीबद्ध अडानी पावर को ऋण के रूप में दे दिया। क्या अडानी ग्रुप की अन्य कंपनियों में से पैसे को निकाल कर गुपचुप तरीके से अडानी पावर में ले जाने के लिए आदिकोर्प को महज एक पाइपलाईन के रूप में इस्तेमाल किया गया?

60. इस बात के मद्देनजर कि सूचीबद्ध कंपनियों का बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज कर रहा है, सूचीबद्ध अडानी कंपनियों ने अडानी की एक प्राइवेट कंपनी ''अडानी इन्फ्रास्टक्चर मैनेजमेंट सर्विसिज'' को पिछले 5 वर्षों में 21.1 बिलियन रुपए (260 बिलियन अमरीकी डॉलर) का भुगतान क्यों किया है?

61. सूचीबद्ध कंपनी अडानी एंटरप्राइजिज ने एक ऐसी कंपनी को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया जो अन्ततोगत्वा ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड (जो एक कुख्यात कैरिबियन टैक्स हेवन है) में अडानी परिवार के एक निजी ट्रस्ट की कंपनी है। इसके लिए तर्क दिया गया है कि यह एक ऑस्ट्रेलियन कोयला टर्मिनल को इस्तेमाल करने के लिए एक जमानत राशि (सीक्योरिटी डिपोजिट) के भुगतान के लिए है। सूचीबद्ध कंपनी को अडानी के प्राइवेट हितों को इतनी बड़ी फीस देने की जरूरत क्यों पड़ी?

62. अडानी एंटरप्राइजिज के पिछले 8 वर्ष के दौरान 5 मुख्य वित्त–अधिकारी रहे हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो संभावित एकाउंटिंग अनियमितताओं की तरफ इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अडानी को क्या समस्याएं रही कि वह अपने सर्वोच्च वित्त–अधिकारी के पद पर किसी एक व्यक्ति को काफी समय तक बनाए नहीं रख सकी?

63. इन पिछले सालों में रहे मुख्य वित्त–अधिकारियों में से हरेक के त्यागपत्र या बर्खास्तगी के क्या कारण थे?

64. पिछले पांच सालों में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में हरेक में तीन मुख्य अधिकारी रहे जबकि पिछले चार वर्षों में अडानी गैस और अडानी ट्रांसमिशन, दोनों कंपनियों में भी मुख्य वित्त–अधिकारी बार–बार बदले गए। अडानी को क्या समस्याएं रही कि वह अपने सर्वोच्च वित्त–अधिकारी के पद पर किसी एक व्यक्ति को काफी समय तक बनाए नहीं रख सकी?

65. इन पिछले सालों में रहे इन मुख्य वित्त–अधिकारियों में से हरेक के त्यागपत्र या बर्खास्तगी के क्या कारण थे?

66. अडानी एंटरप्राइजिज और अडानी गैस की स्वतंत्र ऑडिटर शाह ढंढारिया नामक एक छोटी–सी फर्म है। इसके पुरालेख (हिस्टोरिकल आकाईव्ज) दिखाते हैं कि उसके केवल 4 हिस्सेदार और 11 कर्मचारी थे। लगता है कि उसका कोई वर्तमान वेबसाइट नहीं है। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि यह फर्म मासिक कार्यालय किराए के रूप में 32,000 रुपए (435 अमरीकी डॉलर (2021 में)) चुकाती है। केवल एकमात्र अन्य कंपनी, जिसका वह ऑडिट करती है, उनका बाजार पूंजीकरण लगभग 640 मिलियन रुपए (7.8 मिलियन अमरीकी डॉलर) का है। अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों की, सैंकडों सब्सिडिरियां हैं और उनके बीच हजारों इंटररिलेटिड (अंतर्संबंधित) डीलिंगें होती हैं। अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों की इतनी पेचीदागियों के बावजूद, अडानी ने किसी बड़े एवं अधिक विश्वसनीय ऑडिटरों के बजाय इस छोटी–सी और वस्तुतः अज्ञात फर्म को अपने ऑडिटर के तौर पर क्यों चुना?

67. शाह ढंढारिया के जिस ऑडिट–पार्टनर ने अडानी गैस के सालाना ऑडिटों पर हस्ताक्षर किए हैं, जब उसने ऑडिटों को एप्रूव करना शुरू किया तो उसकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। वह विश्वविद्यालय से पढ़कर अभी–अभी निकला था। क्या एक ऐसा व्यक्ति सचमुच इस पोजीशन में था कि वह दुनिया के एक सबसे ताकतवर व्यक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित कंपनियों के हिसाब–किताब का ऑडिट कर सके, उसके वित्तीय कामकाज की जांच–पड़ताल कर सके?

हिन्डनबर्ग रिपोर्ट के अडानी से 88 सवाल

एक सबसे ताकतवर व्यक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित कंपनियों के हिसाब–किताब का ऑडिट कर सके, उसके वित्तीय कामकाज की जांच–पड़ताल कर सके?

69. शाह ढंढारिया के जिन ऑडिट–पार्टनरों ने अडानी गैस और अडानी एंटरप्राइजिज के सालाना ऑडिटों पर हस्ताक्षर किए हैं, वे अब 28 वर्ष के हैं। फिर वही सवाल, क्या एक ऐसा व्यक्ति सचमुच इस पोजीशन में था कि वह दुनिया के एक सबसे ताकतवर व्यक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित कंपनियों के हिसाब–किताब का ऑडिट कर सके, उसके वित्तीय कामकाज की जांच–पड़ताल कर सके?

70. अडानी पावर के ऑडिटर ने, जो अर्नस्ट एंड यंग से संबद्ध है, अपने ऑडिट में एक ''प्रतिबंधक'' राय दी और कहा कि अडानी पावर में 56.75 बिलियन (700 मिलियन अमरीकी डॉलर) से अधिक के जो निवेश हुए हैं और जो ऋण लिए/दिए गए हैं, उनके मूल्य को आंकने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। इन निवेशों और ऋणों के मूल्यांकन (वेल्यूएशन) के लिए अडानी पावर का पूरा मूल्यांकन (वेल्यूएशन) क्या है?

71. अडानी पावर के निवेशों और ऋणों के मूल्यांकन के किस हिस्से से ऑडिटर असहमत थे?

72. अडानी पर डीआरआई और अन्य सरकारी एजेंसियों ने धोखाधड़ी के अनेकानेक आरोप लगाए हैं। 2004–2006 हीरा घोटाला जांच में, सरकार ने आरोप लगाया कि अडानी एक्सपोर्ट्स लि. (जिसका नाम बाद में अडानी एंटरप्राइजिज हो गया) और संबंधित कंपनियों द्वारा किया गया निर्यात इस उद्योग समूह में अन्य तमाम 34 फर्मों द्वारा किए जाने वाले कुल निर्यात का तीन गुना था। ट्रेडिंग वॉल्यूम में उस अचानक वृद्धि को अडानी किस तरह व्याख्या करते हैं?

73. हीरा जांच ने विनोद अडानी और यूएई, सिंगापुर एवं हांगकांग की उन कंपनियों द्वारा अदा की गई भूमिका को भी प्रदर्शित किया गया जिनका इस्तेमाल पैसे और उत्पाद के इधर–उधर संचालन को सुसाध्य एवं सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों के साथ जो ट्रेडिंग की गई, उस तमाम के संबंध में अडानी का क्या जवाब हैं?

74. 2011 में, कर्नाटक राज्य के लिए संसदीय जांच अधिकारी ने 466 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी को 600 बिलियन रुपए (12 बिलियन अमरीकी डॉलर) के बहुत बड़े घोटाले के ''अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दू'' के तौर पर वर्णित किया गया। इस घोटाले में लौह अयस्क के गैर–कानूनी आयात का मामला भी शामिल था जिसमें आरोप था कि इस स्कीम कोअमली जाता पहुंचाने में मदद के लिए अडानी ने सरकार को हर स्तर पर रिश्वत दी थी। इस जांच और इन निष्कर्षों के हिस्से के तौर पर प्रस्तुत सुविस्तृत सबूतों के संबंध में अडानी का क्या जवाब है?

75. 2014 में, डीआरआई ने एक बार फिर अडानी पर आरोप लगाया था कि उसने पैसा साइफन (चोरी–छिपे देश के बाहर ले जाने/अंदर लाने) के लिए विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित/संचालित मध्यवर्ती यूएई आधारित शैल कंपनियों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में, यह काम पावर उपकरणों की ओवर–इन्वॉयसिंग के जरिये किया गया। क्या अडानी ने इलेक्ट्रोजेन इन्फ्रा एफजेडई जैसी यूएई आधारित कंपनियों के लिए पावर उपकरण खरीदों को इन्वॉयस किया था? यदि ऐसा था, तो क्यों?

76. उपकरणों के लिए शुरू में जो खरीद कीमत थी, क्या उसे बाद में बढ़ाया गया? विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों ने वह कौन–सी सेवाएं प्रदान की थी, जो इस मूल्य वृद्धि को उचित ठहरा पाएं?

77. डीआरआई की उसी जांच से पता लगा कि विनोद अडानी की मध्यवर्ती कंपनी ने अडानी की एक निजी मिल्कियत की और मॉरिशस आधारित कंपनी को 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक ऋण दिया। इन ट्रांजेक्शनों के लिए क्या जवाब है?

78. जब यह पैसा मॉरिशस में अडानी की कंपनी को भेजा गया, उसके बाद इन ट्रांजेक्शनों से मिलने वाला पैसा कहां गया?

79. डीआईआर जांच ने विनोद अडानी की मध्यवर्ती कंपनियों के जरिये अनेक अन्य ट्रांजेक्शनों के बारे में भी दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। इन ट्रांजेक्शनों के लिए अडानी का क्या स्पष्टीकरण है?

80. एक अन्य घोटाले में अडानी पर दुबई, यूएई, सिंगापुर और बीवीआई में शैल कंपनियों के जरिये कोयला आयातों के अधि–मूल्यांकन (ओवर–वेल्यूइंग) का आरोप लगाया गया था। क्या अडानी ने इन स्थानों की कंपनियों के साथ ट्रांजेक्शन किए थे? यदि किए थे, तो कौन–थे और क्यों?

81. 2019 में, सिंगापुर की कंपनी पान एशिया कोल ट्रेडिंग को अडानी ग्रुप द्वारा जारी टेंडर पर कोल सप्लाई का ऑर्डर मिला। पान एशिया कोल ट्रेडिंग वेबसाइट में इसके कोयला ट्रेडिंग के अनुभव के बारे में कोई विवरण नहीं दिए गए हैं और न ही इस कंपनी के साथ जुड़े एक भी व्यक्ति का नाम दिया गया है। अडानी ग्रुप ने कोयला सप्लाई के लिए ऐसी छोटी फर्म को क्यों चुना? इसके चयन में क्या जरूरी एहतियात बरती गयी?

82. कारपोरेट रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अडानी ग्रुप कंपनी का एक पूर्व डायरेक्टर पान एशिया का एक डायरेक्टर और शेयर होल्डर था। अडानी ग्रुप ने ट्रांजेक्शन में इससे हित के संभावित टकराव को क्यों नहीं डिस्क्लोज किया?

83. सिंगापुर के कारपोरेट रिकॉर्डों के अनुसार, उसने 2019 में जिस साल कोयले का सौदा प्राप्त किया था, पान एशिया कोल ट्रेडिंग ने अडानी ग्रुप की एक प्राइवेट कंपनी को 30 मिलियन डॉलर का ऋण दिया। जिस समय इसकी सूचीबद्ध कंपनी उसके साथ कोयला सप्लाई का डील कर रही थी, ठीक उसी समय अडानी परिवार की एक प्राइवेट कंपनी ने सिंगापुर में एक छोटी एकल शेयर होल्डर कंपनी से पैसा क्यों लिया?

84. अपने साक्षत्कारों में, गौतम अडानी ने कहा है कि ''आलोचना के प्रति मैं अत्यंत खुला दिमाग रखता हूं''। इसके मद्देनजर, जब समालोचनात्मक पत्रकार परंजोय गुहा ने अडानी टैक्स वंचना के आरोप पर लेख लिखे तो उसके बाद अडानी ने उसे जेल क्यों भिजवाया?

85. उसी साक्षत्कार में, गौतम अडानी ने कहा कि ''प्रत्येक आलोचना मुझे स्वयं में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है।'' जब ऐसा है, तो

कंपनी का नाम	स्थान	कब बनी	मुख्य डायरेक्टर संबंध जिसकी पहचान की गई
एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.04.27	विनोद अडानी
इफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2015.10.09	सुबीर मित्रा
ऑल्ट्रोज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2021.04.29	सुबीर मित्रा
एस्सेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2010.10.04	विनोद अडानी
एस्सेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2008.06.09	विनोद अडानी
एथेना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.07.18	सुबीर मित्रा
एथेना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2017.07.08	सुबीर मित्रा
अंटलांटिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2017.02.18	विनोद अडानी
बिर्च ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2021.10.19	सुबीर मित्रा
ब्रह्म ओपर्चुनिटीज ए.लि.	मॉरिशस	2007.11.26	विनोद अडानी
कोन्कोर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2009.02.16	विनोद अडानी
डेल्फिनियम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2021.02.02	सुबीर मित्रा
डोम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.08.18	विनोद अडानी
एफिकेसी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2018.01.19	विनोद अडानी
एन्डेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2021.04.29	सुबीर मित्रा
फर्वेन्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2018.01.19	विनोद अडानी
फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.08.18	सुबीर मित्रा
फोर्टिट्यूड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.08.18	सुबीर मित्रा
गार्डेनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2021.02.02	सुबीर मित्रा
ग्लोबल रिसोसिज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स	मॉरिशस	2015.10.09	विनोद अडानी
ग्रोमोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.	मॉरिशस	2010.09.15	चांग चुंग लिंग
ग्रोथ ट्रेडिंग एंड वेंच प्रा.	मॉरिशस	2009.10.23	विनोद शांतिलाल शाह
हरमोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2020.11.17	सुबीर मित्रा
हिबिस्कस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2021.04.29	सुबीर मित्रा
इनफिनिट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2021.02.02	सुबीर मित्रा
जुवेन्ट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2020.12.03	सुबीर मित्रा
कृणाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2005.10.04	विनोद अडानी
लिंगो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	मॉरिशस	2009.12.10	चांग चुंग लिंग
ओएसिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.08.21	विनोद अडानी
ओर्बिट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट	मॉरिशस	2017.08.18	विनोद अडानी
पान एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2017.08.08	सुबीर मित्रा
प्रिम रोज ट्रे एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2021.02.02	सुबीर मित्रा
रिसोर्स एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2011.04.18	विनोद अडानी
रोसर्जन्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2020.12.03	सुबीर मित्रा
रोबस्ट ट्रेडिंग एंड वेचर प्रा. लि.	मॉरिशस	2009.10.23	विनोद शांतिलाल शाह
वेन्चुरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2007.08.08	विनोद शांतिलाल शाह
विर्चु ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि.	मॉरिशस	2011.01.31	विनोद अडानी
वर्ल्ड वाइड एमर्जिंग मार्केट होल्डिंग	मॉरिशस	2015.10.30	सुबीर मित्रा

नोट: इस रिपोर्ट के अंत में यह डिस्क्लोजर दिया गया है कि हिन्डनबर्ग अमरीका ट्रेडिड बाँडों और गैर–भारतीय ट्रेडिड डेरिवेटिव इन्स्ट्रुमेन्ट्स के जरिए अडानी ग्रुप में शार्ट पोजिशनें रखता है।

2021 में, अडानी ने उस यू–ट्यूबर, जिसने अडानी के छिप्रान्वेषी विडियो बनाए, के खिलाफ अदालत से आगे चुप रहने का आदेश क्यों हासिल किया?

86. उसी साक्षत्कार में, गौतम अडानी ने कहा कि ''मैं हमेशा आत्म–निरीक्षण करता हूं और अन्य के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता हूं''। जब ऐसा है, तो अडानी ग्रुप ने उन पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ वे कानूनी मामले क्यों दायर किए जिनकी मीडिया हितों पर नजर रखने वालों द्वारा आलोचना की गई है? उसने ऑस्ट्रेलिया में एक एक्टिविस्ट के खिलाफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्यों लगाए?

87. यदि अडानी ग्रुप के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो वह अपने छोटे–से–छोटे आलोचक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई चलाने की जरूरत क्यों महसूस करता है?

88. क्या अडानी ग्रुप अपने–आप को सच में मजबूत कारपोरेट गवर्नेस के साथ एक ऐसे संगठन के रूप में देखता है जो जो अपने नारे ''ग्रोथ विद गुडनेस'' (अच्छाई के साथ वृद्धि) को साकार करता है?

परिशिष्ट 1: कम से कम 38 मॉरिशस शैल कंपनियों में विनोद अडानी की लिप्तता

पूरी की पूरी मॉरिशस कारपोरेट रजिस्ट्री को कैटेलॉग करने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि पिछले दो दशकों के दौरान मॉरिशस में ऑफशोर शैल कंपनियों में विनोद अडानी की लिप्तता बहुत बड़ी रही है।

नीचे हम 38 मॉरिशस आधारित कंपनियों की पहचान करते हैं जिनमें विनोद अडानी एक डायरेक्टर और /या लाभ प्राप्तकर्ता मालिक है या जिनमें उसके साथ नजदीकी से जुड़े लोग डायरेक्टर हैं। नजदीकी से जुड़े इन लोगों में सुबीर मित्रा शामिल है जिसका नाम अन्य अपारदर्शी सभी स्थानों में विनोद अडानी–नियंत्रित कंपनियों में आता है और जो, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, अडानी परिवार कार्यालय का प्रमुख है।

एक अन्य व्यक्ति है चांग चुंग लिंग जो एक समय विनोद अडानी के साथ आवासीय पता शेयर करता था। वह उन कंपनियों में डायरेक्टर भी था जिन्होंने, डीआरआई जांचों के अनुसार, सार्वजनिक तौर पर सूचीबद्ध अडानी कंपनियों से पैसा साइफन करने के लिए, जो अंततः विनोद अडानी के फायदे के लिए था, कथित तौर पर धोखाधड़ी की स्कीमों का इस्तेमाल किया।

इनमें से अनेक कंपनियों में कारपोरेट कामकाज का कोई सार्थक निशान तक नहीं: कोई वेबसाइट नहीं; सार्वजनिक तौर पर जगजाहिर कर्मचारी नहीं, कोई स्वतंत्र पता नहीं या उनकी इन कारपोरेट फर्मों से अलग कोई बुनियादी संपर्क जानकारी नहीं।

साथ में लीगल डिस्क्लेमर भी दिया गया है और दावा किया गया है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रिपोर्ट में दी गई सभी जानकारियां सही और विश्वसनीय हैं। (समाप्त)

आदिवासियों, दलितों और खेत मजदूरों का राजभवन पर प्रदर्शन

उदयपुर: आदिवासियों, दलितों और खेत मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में राज्य भर से आए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य के 9 संगठनों ने आयोजित किया था।

इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम सिंह तावड, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राजस्थान राज्य कमेटी के अध्यक्ष रामरतन बागड़िया, राजस्थान खेत मजदूर यूनियन के राज्य संयोजक अवतार सिंह रामगढ़िया, दलित शोषण मुक्ति मंच के किशन मेघवाल, अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन के विकास कुमार मीणा, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राजवीर कुतड़िया, आदिवासी जनाधिकार एका मंच के विमल भगोरा, भीम संसद इंडिया के दयात चंद भाटी, राजस्थान मजदूर किसान यूनियन आदि ने किया।

प्रदर्शन के बाद दिये गये ज्ञापन मे 28 सूत्रीय मांगो को उठाया गया था। जिसमें मुख्य मांगें – दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर रोक, आदिवासी क्षेत्र में वन मान्यता अधिकार कानून 2005 के तहत सभी को उनकी जमीन के पट्टे दिये जाएँ और बेदखली बंद की जाए, सभी को रहने के लिए जगह –आवासी घरों के पट्टे–बस्तियों को नियमित किया जाये, प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जाने वाली राशि 5 लाख की जाये, खाद्य सुरक्षा योजना में सभी वंचितों को राशन कार्ड उपलब्ध हों, दलित, मुसलमानों और ईसाईयों के लिए आरक्षण दिया जाये, अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजनाओं को पुनः लागू किया जाये, भूमि हदबंदी कानून को लागू कर भूमिहीनों को जमीन दी जाये, मनरेगा में 300 दिन काम और 600/– रू प्रतिदिन मानदेय दिया जाये, नई शिक्षा नीति निरस्त की जाये, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये आदि शामिल थीं।

इस प्रदर्शन में उदयपुर से घनश्याम सिंह तावाड के नेतृत्व में लगभग 70 लोगों के एक दल ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने जम कर मोदी सरकार की आम जन विरोधी, आदिवासी, मजदूर, दलित, महिला, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों की आलोचन की। वक्ताओं ने मोदी सरकार की देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये देश को बेचने के नीतियां हैं और देश की जनता से साथ गद्दारी है, इस नीति से रोजगार में भारी कमी आई है जिससे बेरोजगारी बढ़ी है, मोदी सरकार केवल अदानी और अंबानी जैसे अमीरों के हितों में ही नीतियां बना रही है तथा मजदूर किसानों दलितों आदिवासियों को गुलाम जैसी जिंदगी बिताने की कवायद कर रही है। देश की आम जनता इनकी चालों को समझ चुकी है और इनसे मुक्ति चाहती है। अंत में महामहिम राज्यपाल को अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन दिया।

30 मई को संसद अभियान सफल बनाने का आह्वान

सुबोध दत्ता

कोलकत्ता: पश्चिम बंगो राज्य खेत प्रमुख यूनियन द्वारा 21 मार्च को भूपेश भवन के लाहिड़ी मुखर्जी हॉल में राज्य खेत मजदूर और दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 30 मई को संसद अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया।

इस सम्मेलन की अध्यक्षता बीकेएमयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मुस्तफा रहमान ने की।

बैठक में राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव तपन गांगुली ने मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया। खेत मजदूरों और दलितों के सामाजिक संरक्षण की अन्य मांगों के साथ–साथ काम का अधिकार और मजदूरी में वृद्धि उनमें से कुछेक मांगें हैं।

मनरेगा में साल में 200 दिन काम, रु. 600 प्रतिदिन मजदूरी की मांग की गई। दलितों की होने वाली हत्या और उन पर अत्याचारों को समाप्त करने, मॉब लिंचिंग और देश में जल, भूमि और जंगल के अधिकारों को लागू करने, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए केंद्रीय आवंटन में वृद्धि, लोगों के बीच विभाजन, हिंसा, घृणा और हिंसा को समाप्त करने सहित कई मांगें रखी गई। भाकपा के राज्य सचिव स्वपन बनर्जी ने इन मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि खेत मजदूरों और दलितों का यह सम्मेलन निस्संदेह राज्य खेत मजदूर यूनियन की ओर से एक सकारात्मक कदम है. हमारे राज्य में भी जाति की राजनीति फैल चुकी है। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। भाकपा ने 15 अप्रैल से 14 मई तक देशभर में मार्च निकालने का कार्यक्रम लिया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खेत मजदूर यूनियन को भी सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभानी है। सबकी मांगें, सबकी समस्याएं सुनी जाएं। लोगों को दृढ़ रहना चाहिए।

खेत मजदूर, दलित कन्वेंशन

भाजपा सरकार देश की संपत्ति बेच रही है। अडानी–अंबानी की संपत्ति रॉकेट की गति से बढ़ रही है। कमोडिटी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे राज्य में टीएमसी सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। उन्होंने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्रायोजित संस्थानों में भर्तियों और नियुक्तियों को बेचने की दुकानें खोल ली हैं। कई मंत्री, नेता अब मुकदमे के तहत हिरासत में हैं। इन दोनों बुराइयों से लड़ना चाहिए।

पश्चिम बंगा राज्य खेत मजदूर यूनियन द्वारा भूपेश भवन में आयोजित खेत मजदूरों और दलितों के इस सम्मेलन में भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय परिषद के सचिव वीएस निर्मल ने 30 मई को संसद अभियान की सफलता का आह्वान किया. भारत की कुल जनसंख्या खेतिहर मजदूर और दलित हैं। और ज्यादातर दौलत अमीरों और कारपोरेट्स के हाथ में है। जमीन पर फसल उगाने वाले जमीन के मालिक नहीं होते, जमीन के मालिक वो होते हैं जिनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। दलित–खेत मजदूरों को भूखे पेट आधा–अधूरा गुजारा करना पड़ रहा है। इन सभी भूमिहीन, बेघर, अशिक्षित लोगों को इंसानों की तरह रहने का माहौल देना चाहिए। और इस संबंध में बीकेएमयू को एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी होगी।

राज्य खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव सुबीर मुखर्जी ने कहा कि हमारे देश की सभ्यता खेतिहर मजदूरों, दलितों और आदिवासियों के कंधों पर आगे बढ़ रही है. और वे समाज में पीछे हैं। उन्हें उनका हक वापस दिया जाए।

सम्मेलन को कल्याण बनर्जी, विद्युत गांगुली, मनोरंजन मंडल, सुभाष पात्रा और निहार मृधा ने संबोधित किया। संगीत अब्दुल कादर लश्कर ने दिया था। शाम को खचाखच भरे दर्शकों के साथ अधिवेशन का समापन हुआ।

वाम–लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करने का प्रयास करेगी भाकपा

अरविन्द राज स्वरूप

लखनऊ, 21 मार्च 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य काउंसिल की दो दिवसीय बैठक यहां राज्य कार्यालय पर संपन्न हुयी। बैठक की अध्यक्षता इम्तेयाज अहमद (पूर्व विधायक), कान्ति मिश्रा एवं अमित यादव के अध्यक्षमंडल ने की।

प्रारंभ में बैठक को भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं प्रभारी डॉ. गिरीश ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गत शताब्दी के नौवें दशक के अंत में सोवियत संघ के बिखराव के बाद एकध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया था। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका की दादागिरी निर्बाध रूप से चल पड़ी। अतःएव अमेरिका ने मनमाने तरीके से इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया में कहर बरपाया और इन देशों को तबाह कर दिया। साथ ही सैन्य गठबंधन 'नाटो' का विस्तार भी करता रहा। अपनी और 'नाटो' की ताकत के बल पर उसने रूस के व्यापरिक हितों को नुकसान पहुंचाने को हर तरह से घेराबन्दी की और यूक्रेन आदि रूस के पड़ोसी देशों को नाटो में शामिल करने की साजिश रची। हर तरफ से घिरा देख रूस ने यूक्रेन में सामरिक हस्तक्षेप किया जो आज एक युद्ध का रूप ले चुका है। यूक्रेन में धन जन की भारी हानि हुयी है। शान्ति के लिए पहलकदमी करने के बजाय अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को तमाम युद्ध सामग्री दे रहे हैं। जिससे युद्ध लम्बा खिंच रहा है।

अमेरिका की एकध्रुवीयता को अब रूस, चीन, ईरान आदि से चुनौती मिलने लगी है,जिससे वह बौखलाया हुआ है। उसकी नीति से विश्व में कई जगह तनाव क्षेत्र बन गये हैं और विश्व शान्ति को खतरा पैदा हो गया है। हमें विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण प्रयास करते रहना है ताकि मानव विकास का रास्ता हमवार हो।

डॉ. गिरीश ने कहा कि भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारें जनता को तबाह कर रही हैं। महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी सभी को पंख लगे हैं। अडानी घोटाले पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लोकतंत्र को कुचलते हुये जनता और विपक्ष की आवाज दबाने को ईडी, सीबीआई आदि संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को बांटने और दबाने को सांप्रदायिकता को उभारा जा रहा है। आज लोगों को, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा। इसके लिये समस्त लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। विपक्ष के अलग अलग प्लेटफार्म भाजपा को लाभ पहुंचाएंगे। भाकपा वामपंथी एकता को मजबूत करते हुऐ लोकतांत्रिक शक्तियों की कार्यक्रम आधारित एकता बनाने के लिये गंभीर प्रयास करेगी।

भाजपा को 2024 में परास्त करने की रणनीति

देश और उत्तर प्रदेश के हालातों पर राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं के सवालों से किनारा कर रही है। लोगों को बुलडोजर का भय और आकर्षण दिखाकर, धर्म के नाम पर आस्था का दोहन कर, आरक्षण को बदल कर लोगों को बरगलाने में जुटी है। भाकपा हर कदम पर उसका पर्दाफाश कर रही है।

उन्होंने केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके अनुसार डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल से समूचे उत्तर प्रदेश में जिला कमेटियों द्वारा पदयात्राएं की जायेंगी और साथ साथ जनता से पार्टी संचालन के लिए फंड मांगा जायेगा। जनता के ज्वलन्त सवालों को उठाते हुए लोगों को भाजपा के खिलाफ मतदान करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इस अभियान के इस चरण का समापन 15 मई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आदि आयोजित कर किया जायेगा।

राज्य काउंसिल ने निकाय चुनावों की तैयारी की समीक्षा की और बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया। लोकसभा की सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जताते हुए उन पर तैयारियां तेज करने का निश्चय किया गया।

एक प्रस्ताव पारित कर लगातार हो रही बारिश ओलावृष्टि और तूफान से तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और सरकार से फसल हानि की शत प्रतिशत भरपाई की मांग की गई।

एक अन्य प्रस्ताव में राज्य मंत्रिमंडल के उस फैसले की निन्दा की गई जिसमें दलितों आदिवासियो की जमीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लिए जाने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इस निर्णय को तत्काल रदद् करने की मांग की गयी। साथ ही किसानों आदिवासियों की जमीनें हड़पने के उद्देश्य से धारा 80 को समाप्त करने की निन्दा भी की और इस फैसले को भी रद्द करने की मांग की। तीसरे प्रस्ताव में बिजली कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को पूरा कराने को की गयी सफल और शांतिपूर्ण हड़ताल के लिए उन्हें बधाई दी। राजसत्ता के विभिन्न अंगों ने जिस क्रूरता से इस हड़ताल को समाप्त कराने की कोशिश की और मजदूर वर्ग पर दमनचक्र चलाया, भाकपा उसकी कड़े शब्दों में निन्दा करती है।

राज्य काउंसिल ने अखिल भारतीय शान्ति एवं एकजुटता संगठन (ऐप्सो) की राज्य स्तरीय पहलकदमी समिति द्वारा शान्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने और संगठन का विस्तार करने को किये जा रहे प्रयासों के प्रति एकजुटता व्यक्त की तथा सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया। अप्रैल – मई में ऐप्सो के जिला सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे और राज्य सम्मेलन जून माह में मथुरा में आयोजित किया जायेगा।

अछूत का सवाल

भगत सिंह

(काकीनाडा में 1923 मे कांग्रेस–अधिवेशन हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों 'अछूत' कहा जाता था, हिन्दू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बाँट देने का सुझाव दिया। हिन्दू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्गभेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे। इस प्रकार अछूतों के यह 'दोस्त' उन्हें धर्म के नाम पर बाँटने की कोशिशें करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगतसिंह ने 'अछूत का सवाल' नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिये गये हैं। भगतसिंह का यह लेख जून, 1928 के 'किरती' में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था।)

हमारे देश–जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब–अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत–समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा! उनके मन्दिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे! कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआँ अपवित्र हो जाएगा! ये सवाल बीसवीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है।

हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इन्कलाब की आवाज उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटा कर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा–परमात्मा के वजूद को लेकर चिन्तित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा? वे वेद–शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रजों के समान नहीं समझता। लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है?

सिन्ध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मुहम्मद ने, जो बम्बई कौंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खूब कहा–

वे कहते हैं कि जब तुम एक इन्सान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की माँग करो? जब तुम एक इन्सान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार माँगने के अधिकारी कैसे बन गए?

बात बिल्कुल खरी है। लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है इसलिए हिन्दू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बना कर अपने में शामिल करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया–बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहाँ उनसे इन्सानों–जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिन्दू कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, व्यर्थ होगा।

कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुन कर सभी तिलमिला उठते हैं। ठीक इसी तरह की चिन्ता हिन्दुओं को भी हुई। सनातनी पण्डित भी कुछ–न–कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच–बीच में बड़े 'युगांतरकारी' कहे जानेवाले भी शामिल हुए। पटना में हिन्दू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपतराय– जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं– की अध्यक्षता में हुआ, तो जोरदार बहस छिड़ी। अच्छी नोंक–झोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं? तथा क्या उन्हें वेद–शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े–बड़े समाज–सुधारक तमतमा गये, लेकिन लालाजी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिन्दू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो, कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है। हमारी रसोई में निःसंग फिरता है, लेकिन एक इन्सान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज–सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या–क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किये बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं! क्या खूब यह चाल है! सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मन्दिर बना है लेकिन वहाँ अछूत जा घुसे तो वह मन्दिर अपवित्र हो जाता है! भगवान रुष्ट हो जाता है! घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं? तब हमारे इस रवैये में कृतघ्नता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही हम दुरदुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन्सान को पास नहीं बिठा सकते!

आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें साम्प्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुँचाया हो अथवा नहीं लेकिन एक लाभ जरूर पहुँचाया है। अधिक अधिकारों की माँग के लिए अपनी–अपनी कौमों की संख्या बढ़ाने की चिन्ता सबको हुई। मुस्लिमों ने जरा ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बना कर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिन्दुओं के अहम को चोट पहुँची। स्पर्धा बढ़ी। फसाद भी हुए। धीरे–धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जायें। उन्होंने भी अमृत छकाना आरम्भ कर दिया। हिंदू–सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केश कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी–अपनी ओर खींच रही है। इसका बहुत शोर–शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है।

इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी–अपनी खुराक समझ रहा है तो वे अलग ही क्यों न संगठित हो जाएं? इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न हो लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफी हाथ था। 'आदि धर्म मण्डल' जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम हैं।

अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो? इसका जबाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इन्सान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य–विभाजन से। अर्थात् क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है, ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यो ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कह कर दुत्कार दिया एवं निम्नकोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिन्ता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है? चुपचाप दिन गुजारो! इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लम्बे समय तक के लिए शान्त करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सबके प्रायश्चित का वक्त है।

इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गयी। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यो के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुननेवाले भी अछूत समझे जाते हैं। यू. पी. की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं।

इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। बस, समस्या हल हो जाती है। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसा इन्सान समझना, बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना, यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक न देना, कोई ठीक बात नहीं है।

जब गाँवों में मजदूर–प्रचार शुरू हुआ उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझा कर भड़काते थे कि देखो, यह भंगी–चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीन कह कर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है–वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊँचे–ऊँचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गन्दे नहीं रहते। गन्दे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएँ बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जातीं।

लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आपको संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की माँग करना बहुत आशाजनक संकेत हैं। या तो साम्प्रदायिक भेद को झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेम्बलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल–कालेज, कुएँ तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतन्त्रता उन्हें दिलाएं। जबानी तौर पर ही नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बालविवाह के विरुद्ध पेश किए बिल तथा मजहब के बहाने हाय–तौबा मचाई जाती है, वहाँ वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं?

इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जन–प्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार माँगें। हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवको तथा भाइयो! उठो! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविन्द सिंह की फौज की असली शक्ति तुम्हीं थे! शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिन्दा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्यप्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिन्दगी संभव बना कर यह बड़ा भारी अहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैण्ड–एलियेनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती हैं–उठो, अपनी शक्ति पहचानो। संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। (जीवेम्ीव्वनसक इम तिमम उनेज जीमउेमसअमे `जतपाम जीम इसवॅ) स्वतन्त्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इन्सान की धीरे–धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है– 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते'। अर्थात् संगठनबद्ध हो अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इन्कार करने की जुर्रत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुँह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झाँसे में मत फँसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूँजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो... संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो, और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे–धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आन्दोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरो! उठो और बगावत खड़ी कर दो।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

पेज 5 से जारी...

इसका श्रेय (?) जाता है कि उसने रेलवे को इस हद तक बर्बाद कर दिया है।

इस बर्बादी का एक बड़ा कारण रेलवे के विभिन्न कामकाज का निजीकरण भी है। रेलवे के विभिन्न कामों को अनेकानेक ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है और नजर आता है कि वे घुन की तरह रेलवे को खाए जा रहे हैं। रेलवे में स्थायी पदों के खाली पड़े पदों को भरने के बजाय अधिकाधिक काम को ठेके पर कराने का रूझान बढ़ रहा है।

रेल मंत्री दावा करते हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। गजब है कि रेल मंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते नहीं शर्माते। 23 अगस्त 2021 को सरकार ने जिस राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (नेशनल मोनेटाइजेशन पाईपलाइन) नामक योजना की घोषणा की थी उसमें रेलवे की अनेक संपत्तियों को बेचा जाना शामिल है। इन संपत्तियों में शामिल हैं:

– 400 रेलवे स्टेशन;

– 90 यात्री ट्रेनें (150 यात्री ट्रेनों को निजीक कंपनियों को देने की प्रक्रिया अलग से और पहले से ही चल रही है);

– 741 किलोमीटर लंबी कोंकण रेलवे लाईन;

– कालका–शिमला रेलवे लाईन;

– नई जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग हिमालय रेलवे;

– मेट्टापालयम से ऊटी जाने वाली नीलगिरि माउंटेन रेलवे;

– नेरात से माथेरन जाने वाली माथेरन लाईट रेलवे;

– पठानकोट से जोगेन्दनगर जाने वाली कांगड़ा घाटी रेलवे;

– रेलवे की अनेक आवासीय कॉलोनियां;

– रेलवे के 15 स्टेडियम;

– 1400 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी; और

– रेलवे के 265 मालगोदाम (जो कुल गोदामों का 21 प्रतिशत हैं)।

मोदी सरकार को अगर जल्दी सत्ता से नहीं हटाया गया तो अजब नहीं कि भारतीय रेलवे को पूरी की पूरी को बेच दिया जाए!

पुरानी पेंशन स्कीम के लिए महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

14 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। हड़ताल में कर्मचारियों ने इस तरह से जमकर हिस्सा लिया कि सरकार के होश उड़ गए। स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हड़ताली कर्मचारियों से बात करने पर मजबूर होना पड़ा। राज्य सरकार हड़ताल से इस कदर डर गई कि उसे यह आश्वासन देने को मजबूर होना पड़ा कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी जिससे नई पेंशन स्कीम में भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वही पेंशन मिले जो पुरानी पेंशन स्कीम में मिलती है।

सवाल उठता है कि यदि कोई सरकार नई पेंशन स्कीम के तहत भी उतनी ही पेंशन देने की कोई व्यवस्था करना चाहती है जितनी पुरानी पेंशन स्कीम में मिलती है, तो किसी नई व्यवस्था की तलाश करने के बजाय क्यों नहीं पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देती?

सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि एक कमेटी इस समस्या के लिए बैठाई जाएगी जो इस संबंध में शीघ्र–से–शीघ्र रिपोर्ट देगी कि किस प्रकार नई पेंशन स्कीम में भी वही पेंशन दी जाए जो पुरानी पेंशन स्कीम में मिलती है। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर 21 मार्च 2023 को कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी।

भले ही मुख्यमंत्री ने हड़ताल को खत्म करने के लिए ऐसा आश्वासन दिया हो और इस आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी हो, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह पेंशन मिल जाए जो पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलती हैं, यह संभव नजर नहीं आता।

अभी, नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी से उसके वेतन का दस प्रतिशत हिस्सा पेंशन के लिए काट लिया जाता है और उसके वेतन के 14 प्रतिशत के बराबर योगदान पेंशन के लिए सरकार करती है। यह पैसा किसी प्राइवेट पेंशन कंपनी को चला जाता है, जो उस पैसे का कहीं निवेश करती है; उसे जैसा मुनाफा होगा उसके हिसाब से पेंशन देगी; मुनाफा नहीं होगा तो पेंशन मिलने का सवाल ही नहीं। ऐसी स्कीम में सरकार क्या नई बात जोड़ सकती है कि कोई प्राइवेट पेंशन कंपनी उतनी पेंशन दे दें जितनी पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलती है?

इस तरह की खबर आई है कि इसके लिए सरकार अपने योगदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर सकती है। कैसे आश्वस्त हुआ जा सकता है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी कोई प्राइवेट पेंशन कंपनी उतनी पेंशन दे दे जितनी पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलती है? यदि उसने इतना पैसा मिलने के बाद भी कम मुनाफा दिखाया या घाटा दिखा दिया तो पेंशन मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

पुरानी पेंशन स्कीम के स्थान पर नई पेंशन स्कीम लाने के लिए तर्क यह दिया गया था कि सरकार के पास पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। यदि राज्य सरकार पेंशन के लिए अपने योगदान को कर्मचारी के वेतन के 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए तैयार है, तो इसका अर्थ है कि सरकार के पास पेंशन के लिए पर्याप्त पैसा है। तो फिर क्यों नहीं पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर देती?

पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए एक नए संघर्ष का बिगुल

पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए संयुक्त मंच के बैनर तले नेशनल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया है कि देश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करे। यह वस्तुतः एक नए संघर्ष का बिगुल है। वर्षों से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग करते आ रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें (भाजपा से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर) पिछले काफी समय से जिन मांगों के लिए संघर्ष कर रही है और कई बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी कर चुकी हैं, उनमें भी पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग शामिल है।

पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारी इस मांग के लिए अपने संघर्ष को तेज करने की दिशा में चल रहे हैं। नेशनल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन का यह आह्वान उसी दिशा में बढ़ने का कदम है। निश्चय ही इस मांग के लिए सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष आगामी दिनों में एक जुझारू स्वरूप लेने वाला है।

मोदी सरकार का एक जालिमाना फरमान

नेशनल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन द्वारा पेंशन स्कीम की बहाली के लिए प्रदर्शन आदि करने के आह्वान के जवाब में मोदी सरकार ने 21 मार्च 2023 को एक जालिमाना फरमान जारी कर दिया। सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को आगाह किया है कि ये किसी भी विरोध या हड़ताल में शामिल न हों, अन्यथा उन्हें ''परिणाम' भुगतने होंगे। राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद की ओर से 21 मार्च 2023 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच के बैनर तले देश भर में जिला स्तरीय रैलियां आयोजित करने की योजना के मद्देनजर यह चेतावनी दी गई है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को 20 मार्च को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। ये दिशानिर्देश सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने, काम रोकने आदि सहित किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेने या ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाता है, जो सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम–7 का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई निर्णयों में सहमति व्यक्त की है कि हड़ताल पर जाना आचार–व्यवहार नियमों के तहत एक गंभीर कदाचार है और सरकारी कर्मचारियों के कदाचार से कानून के अनुसार निपटने की आवश्यकता है।

आदेश के अनुसार, विरोध प्रदर्शन सहित किसी भी तरह की हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को इसके परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें वेतन में कटौती के अलावा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2022 की धारा 62 में, जिसमें हड़ताल का जिक्र किया गया है, हड़ताल के संबंध में कई किंतु–परंतु लगाए गए हैं (जिनका मकसद हड़ताल करने को असंभव बनाना है), परंतु सीधे तौर पर हड़ताल पर उस तरह रोक नहीं लगाई गई है जिस तरह सरकार के उपरोक्त निर्देशों में लगाई गई है। औद्योगिक संबंध संहिता 2022 में विरोध–प्रदर्शन आदि पर कहीं भी रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा,लोकतंत्र में विरोध एवं असहमति को व्यक्त करना और इसके लिए विरोध प्रदर्शन आदि करने का हरेक व्यक्ति को अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों से उनके इस अधिकार को कैसे छीना जा सकता है?

जहां तक मजदूरों और कर्मचारियों का संबंध है, हड़ताल करना उनका एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण हथियार है। जरूरत पड़ने पर वह हमेशा इस हथियार का इस्तेमाल करते रहे हैं और करते रहेंगे।

बीड़ी मजदूर सभा का जिला सम्मेलन संपन्न

ग्वालियर, 20 मार्च 2023: बीड़ी मजदूर सभा (एटक) का जिला सम्मेलन 19 मार्च 2023 को महिला नेत्री संतो बाई जाटव एवं सोमवती माहौर की अध्यक्षता में सरवटे भवन हजीरा ग्वालियर पर संपन्न हुआ। सम्मेलन में यूनियन के महासचिव हरिशंकर माहौर ने यूनियन के पूर्व में किए गए कार्य और गतिविधियों की रिपोर्ट एवं आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीड़ी मजदूर सभा एटक जिला महासचिव हरिशंकर माहोर ने बीड़ी महिला श्रमिकों का बीड़ी संस्थान प्रबंधकों द्वारा किए जा रहे शोषण,लूट के लिए राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते

हुए उनकी कड़ी निंदा की। उन्होंने उपस्थित बीड़ी श्रमिकों के समूह को संबोधित करते हुए कहा की आज हमारे सामने जो समस्याएं पनप रही है उसके लिए हमें दोहरी लड़ाई लड़ने की तैयारी करने लामबंद होने की आवश्यकता है और उसके लिए अधिक से अधिक यूनियन से साथियों को जोड़ें और यूनियन को मजबूत बनाते हुए प्रबंधकों द्वारा शोषण लूट तथा केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियों के चलते आम जनता की रसोई गैस सहित जीवन उपयोगी वस्तुओं पर अत्यधिक मूल्य वृद्धि के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरना होगा।

सम्मेलन को एटक नेता रमेश सविता ने भी संबोधित किया। सम्मेलन मे आगामी बरसों के लिए 2 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। जिसमें महिला नेत्री हेमलता माहौर को अध्यक्ष, गोमती लिखार, शीला देवी माहोर उपाध्यक्ष, हरिशंकर माहोर महासचिव, श्रीमती रानी गौतम, सुनीता माहोर सचिव, लक्ष्मी देवी कुशवाहा कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी में रमाबाई कोस्टा, सविता कोस्टा, अंगूरी देवी पाल, इमरती देवी जाटव, शकुन बाई जाटव, संतो बाई जाटव, शारदा देवी जाटव, मीना देवी जाटव, मधु देवी, आनंदीबाई शाक्य, मीरा देवी माहौर, ज्योति जाटव निर्वाचित हुई।

भगत सिंह और हमारा समय

सेवाराम त्रिपाठी

'क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी नहीं खत्म होने वाला जन्म– सिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है।' (भगत सिंह)

'रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है।' (भगत सिंह)

शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को याद करते हुए एक अलग तरह का अनुभव और देश के प्रति समर्पित होने का जज्बा पैदा होता है। भारत के इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन का बहुत संजीदा महत्त्व है। वह इसलिए कि एक लंबे समय की गुलामी के बाद आजादी के लिए कुर्बानी का एक जज्बा और संकल्प पैदा हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन ने सोच विचार के क्षेत्र में और अपना मनोविज्ञान निर्मित करने के संदर्भ में अनगिनत प्रयास भी किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन कोई झटपट का आंदोलन कतई नहीं है। यूं तो थोड़े बहुत प्रयास 1857 के पूर्व भी हुए थे। लेकिन वे मात्र प्रयास थे, कोई स्पष्ट रूप नहीं हो पाया था गुलामी के दौर में। शोषण उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कोई सुचिंतित धारणा विकसित नहीं हो पाई थी। कोई उसकी ठोस वास्तविकता भू नहीं उभर पाई थी। अन्याय, दमन बहुत था, जो भारतीय जनता के साथ लगातर संबद्ध रहा है। भारत में रहने वाले किन–किन परिस्थितियों और जीवन के विविध आयामों, कठिनाइयों और दिक्कतों से जूझे हैं। इसकी सघन परछाइयां हमारे जीवन में और इतिहास में भयावह तरीके से दर्ज हैं और संघर्षो के साथ हमारी सांस्कृतिक अस्मिता से संबद्ध होकर जीवन का यथार्थ तो बनी ही बल्कि अभिन्न हिस्सा हो गई हैं। समूचे देश में आक्रोश की एक नई तरह की फिजा बनती गई। इसका अपना संघर्ष भी है सुख भी है और सपना भी है। आजादी की प्राप्ति के बाद क्रमशः कुछ ऐसी स्थितियां बनती, बदलती और दूरगामी प्रभाव छोड़ती गई। वे बार–बार हमें सब कुछ ठीक से देखने और अपनी वास्तविकता की तरफ झांकने का अवसर प्रदान करती हैं।

23 मार्च इस देश के हर आदमी के लिए एक विशेष महत्व का दिन है। इस दिन को हर आदमी अपनी स्मृति में रखने के लिए आतुर है, जो इस देश को खुशहाल देखना चाहता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, और सुखदेव को फांसी दी गई थी। मेरे जेहन में तमाम वे सभी क्रन्तिकारी बार–बार याद आते हैं जिन्होंने, हमें गुलामी के खिलाफ लड़ना सिखाया था। हमें हौसला दिया था। ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। समूचे भारत के वे क्रांतिकारी आंदोलन के वीर सपूत थे। लेकिन ये कुछ नाम हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ के नाम उजागर हो सके। कितने अनाम और बेपहचाने से रह गए लोग भी हैं। वे हमारी इसी धरती में दफन हैं। क्या आप समझते हैं कि आजादी हमें यूं ही उपहार में अंग्रेज सौंप गए थे। जैसा इस दौर का निजाम हमें समझा रहा है। बेहद गंभीर लंबे संघर्ष और उत्कट जिजीविषा के बाद इसे हमनें हासिल किया था। इस देश मेंआजादी और जनतंत्र के लिए, अमन चैन की बहाली का संघर्ष अब भी जारी है। ये ऐसे लोग रहे हैं जो हमारी अनेक पीढ़ियों को अनवरत प्रभावित करते रहेंगे और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। यह सिलसिला कभी थम ही नहीं सकता?

1931 के बाद भी लगातार आंदोलन होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। जब तक हमारे देश भारत में असमानता, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, भूख–गरीबी होगी, तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। भगत सिंह के पहाड़े रटने से उनका महत्व कोई साबित नहीं कर सकता। सोचने की बात है कि आजादी मिलने के इतने सालों बाद भी हम क्या बहुत सारी चीजों से उबर सके हैं। संकीर्णताएं, अंधविश्वासों, गलत मनोविज्ञान और नीचताओं से देश भरा पड़ा है। संवेदनाएं दिन पर दिन भोंथरी हो रही हैं। ऐसा लगता है कि हम भेड़ियाधसान प्रवृत्ति में बुरी तरह गिरफ्त हैं। सच से आंख मिलाने की ताकत धीरे–धीरे कम होती जा रही है। लिखत–पढ़त, राजपाट और खुशहाली के वायदे अपनी जगह हैं। उनकी तमाम तरह की खाता–खतौनिया दहाड़ रही हैं। लेकिन असली हकीकत क्या है? कब से हम नारे लगा रहे हैं कि–'अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं/सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 'उसीके साथ यह भी कि 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है/देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक अंतर्राष्ट्रीय गीत भी हम अक्सर गुनगुनाते हैं, 'हम होंगे कामयाब एक दिन'। क्या वाकई ऐसा हो पाया? क्या यह हम सबके सपनों में ही रहेगा? क्या केवल कथनी करनी में इसी तरह एक लंबी दरार रहेगी। बहरहाल, बातें बहुत हैं।

22 मार्च1931 को शहीद भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्र में लिखा था–'साथियो, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। कैद होकर या पाबन्द होकर न रहूं। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रन्तिकारी दलों के आदर्शो ने मुझे बहुत ऊँचा उठा दिया है इतना ऊँचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊँचा नहीं उठ सकता था। 'पत्र बड़ा है लेकिन उसमें छिपी भावनाएं हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। शहीदों की चिताएं जहां जली थी या फांसी के फंदों पर जो झूले थे अब वहां मेले लगेंगे या नहीं। मेले लगने के कहीं कोई लक्षण दिखाई नहीं देते? जो सत्ता में काबिज होता है। वह अपने मन के और स्वार्थो के मेले लगाता है। उसे न भगत सिंह एवं अन्य क्रान्तिकारियों से कोई लेना देना है और न स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत से और न भारतीय संस्कृति और सभ्यता से। न वास्तविक जीवन मूल्यों से। राजपाट चलाए जाने के मंसूबे अलग हुआ करते हैं और वास्तविकता एकदम भिन्न।

आज भी हमारे आजाद भारत में तरह–तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न ही नहीं प्रश्नों के सैलाब उठ रहे हैं। उन्हें अनवरत थोपा जा रहा है। हम क्या केवल कामयाबी के गाने ही गाते रहेंगे? हमारी बहु प्रतीक्षित बहुआयामी जनपक्षधरता से मतलब न भाईचारे से, न समानता से। भारतीय संविधान की सैद्धांतिकी से न उसके व्यवहार शास्त्र से। संविधान को एक तरह से धुप्पल बना दिया गया है और उसके साथ आजादी का एक जादुई खेल जारी है। जादू टोना टोटका तो एकदम अलग चीज है और जीवन का व्यवहारशास्त्र एकदम अलग।

सत्ता केवल भगत सिंह और उनकी क्रांतिकारिता के नाम पर वोट बटोरना चाहती है। क्या भगत सिंह किसी के लिए वोटों की सीढ़ियां हैं या और कुछ। बदली हुई स्थिति पर भगत सिंह पर पुनर्विचार करने की गंभीरता से जरूरत है। भगत सिंह जी ने जो सपने देखे थे उसमें भूचाल था। उसमें साहस, ताकत और मानवता के प्यार की बिजली भरी थी। उनके सोच में समाज और देश को बदलने की क्रांतिकारी चाहत थी। इतना समय गुजर जाने के बाद भी आज भी समूचा देश उनके बलिदान को बड़ी गम्भीरता और सम्मान के साथ याद करता है। सवाल है कि आजादी के इस नायाब दीवाने को कोई कैसे भूल सकता है? मैं उन्हें स्वतन्त्रता का बिजली घर मानता हूं। उनकी तड़प को बार–बार सलाम करता हूं। तथ्य है कि कुछ घटनाओं ने उनके मन को बहुत गहरे तक स्पर्श किया था, उसमें 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का वीभत्स हत्याकांड और अंग्रेजों द्वारा किए गए तमाम जुल्म और उनकी श्रृंखला भी शामिल हैं।

वे अत्यंत अध्ययनशील आदमी रहे हैं। भगत सिंह को फिल्में देखने का बेहद शौक था। चार्ली चौपलिन की फिल्में उन्हें प्रभावित करती थीं। उनके द्वारा दिए गए नारे याद कर रहा हूं। मसलन– 'इंकलाब जिंदाबाद, और साम्राज्यवाद का नाश हो।' हमारे समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण जो वैमनस्यता और दूरियां बढ़ रही थीं उनके लिए उनके मन में अपार करुणा और नफरत थी। इस शख्स की समूची जिन्दगी एक प्रयोगशाला रही है। एक जगह उन्होंने लिखा था–'निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं।' उनके लिखे कुछ लेख मेरे अंतः आकाश में अब भी चमक पैदा करते हैं। मसलन– 'मैं नास्तिक क्यों हूं, विद्यार्थी और राजनीति, अछूत समस्या आदि।

आज अपने हकों के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी के रूप में अभिहित किए जा रहे हैं। और उन्हें निकृष्ट कोटि में परिगणित किया जा रहा है। अचानक हरिशंकर परसाई के एक कथन पर मेरा ध्यान गया। 'स्वाधीनता संघर्ष में भगत सिंह, आजाद तथा बंगाल के क्रांतिकारियों की भूमिका बहुत लोग आतंकवादी की भूमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पर भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था–हमारा विश्वास हिंसा में नहीं है। उस छोटी उम्र में भगत सिंह का कितना प्रौढ़ चिंतन था। उनके लेख कितने विचारपूर्ण हैं। उनका संगठन था–हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। भगत सिंह ने जन–आंदोलन को ही स्वाधीनता के लिए जरूरी माना था। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपने आखिरी संदेश में यही लिखा था कि हमें जन–आंदोलन चलाना चाहिए। (ऐसा भी सोचा जाता है– पृष्ठ–104)

सोच–सोचकर हैरानी होती है कि हम प्रजातन्त्र के किस मुहाने पर आ गए हैं। आजादी का निरन्तर चीरहरण हो रहा है और जनतंत्र का अत्यंत तेजी से क्षरण। उसमें प्रश्नकवाचकों के नए–नए रूपाकार हैं। जनतन्त्र किर्चा–किर्चा टूटकर बिखर रहा है। उसे बार–बार छलनी किया जा रहा है। ऐसे वातावरण में हमें भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से रोशनी मिलती है। बहुत कठिन है डगर आजादी और जनतन्त्र की। स्वाधीनता को बचाए रखने की। हम नाटक–नौटंकियों के बीच हैं। यहीं से रास्ता निकलेगा। भगत सिंह जी के आलेख का एक अंश पढें–'मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है और यथार्थवादी बन जाता है तब उसे श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए जिनमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। आज यह मेरी स्थिति है। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरे सोचने का तरीका है, जिसने मुझे नास्तिक बनाया।'

भगत सिंह एक ऐसी हकीकत का नाम है, जिससे शैतान तक थर्राते हैं। उनके ख्यालों, विचारों और साहस से घबराते हैं। उनको किसी भी हालत में पचा पाना बड़ा आसान नहीं होता। भगत सिंह के तेजस्वी स्वर के सामने उनकी घिग्घी बंधी रहती है। राष्ट्रवाद की जाजिम में सबको खींचकर ये नए–नए तोपची देशभक्ति का राग अलापते आ रहे हैं। भगत सिंह एक असहजता और असुविधा का भी नाम है। वे अपने जीवन में विचारों का बिजलीघर रहे हैं। नाटक और नौटंकियों का प्रदर्शन कर के भगत सिंह की शहादत को न तो भुनाया जा सकता और न उन्हें मात्र गाया बजाया जा सकता? भगतसिंह हर प्रलोभन की काट का नाम है। भगतसिंह सच्चाई और ईमानदारी का सर्वोत्कृष्ट शिखर भी है।

जबसे जानने पहचानने और बूझने लायक हुआ हूं। तब से भगत सिंह के व्यक्तित्व से आत्मीयता और वैचारिक संघर्ष के साथ में हूं। यह तय है कि उनके बारे में विमर्श 23 मार्च के दिन ज्यादा होते हैं। इसीलिए कि यह दिन उनकी पुण्यतिथि का है, शहादत दिवस का भी है। उनके बारे में दीवानगी भारत मे तो है ही पाक और बांग्लादेश में भी है। उनकी शहादत पर प्रश्न उठते हैं। उनकी निर्मलता की बातें होती हैं, जाहिर है कि उनकी देशभक्ति का सानी भी मिलना मुश्किल है। भगत सिंह उस शख्सियत का नाम है जिसे कोई भी प्रलोभन, जिसे कोई भी अर्गला बांध नहीं सकी। मैं शासकीय सेवा में 1982 से 1984 तक पिपरिया में पदस्थ था। वहां शहीद भगत सिंह के नाम से एक पुस्तकालय चला करता था जिसमें क्रांतिकारी साहित्य हुआ करता था। उन पर चर्चा तो जब तब होती ही रहती है। अब शायद पुस्तकालय अस्तित्व में नहीं है। यहां मैं भगत सिंह जी के तीन कथन उद्धृत कर रहा हूं–

1. 'मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता।'

2. प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं।

3. बंदूकों और बमों से क्रांति नहीं आती बल्कि वह विचारों की सान पर तैयार होती है। विजय शंकर चतुर्वेदी ने अपनी फेसबुक में एक कविता लिखी थी। उसका एक अंश प्रस्तुत है– ''शैतानी रूहें, तुम्हारे रोशन ख्यालों से थर्राती हैं/और अपने–अपने खोमचें के राष्ट्रचवाद पर/तुम्हारा पोस्टर चिपकाती हैं/तुम्हारे ख्याल से उनका महज इतना लेना–देना है/कि हर शहादत को उन्होंने बिकाऊ जिन्स में बदल देना है।''

भगत सिंह का प्रभाव और उनकी ख्याति नौजवानों में ही नहीं प्रायः तब्दीली चाहने वाले हर इंसान में रही है। उनके बलिदान को भुलाकर सत्ताओं ने केवल उनकी पुण्यतिथि पर झंडे फहराए, सलामी दी उनके विचारों को शासन सत्ता में और सामाजिक जीवन में न उतारने की कसम खा ली। पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह

शेष पेज 14 पर...

भगत सिंह और हमारा ...

पेज 13 से जारी...

'पाश' ने उन पर एक जीवंत कविता लिखी है। उसकी कुछ पंक्तियां देखें–' 'उसकी शहादत के बाद बाकी लोग/किसी दृश्य की तरह बचे/ताजा मुंदी पलकें/ देश में सिमटती जा रही झांकी सी/ देश सारा बच रहा बाकी/ उसके चले जाने के बाद/ उसकी शहादत के बाद/ अपने भीतर खुलती खिड़की में/ लोगों की आवाजें जम गई/.... उससे संबंधित अपनी उस शहादत के बाद/ लोगों के घरों में, उनकी तकियों में छिपे हुए/ कपड़े की महक की तरह बिखर गया/ शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था ईश्वर की तरह/ लेकिन ईश्वर की तरह वह निस्तेज नहीं था।'

सचमुच हम कौन सी कामयाबी पाना चाहते हैं। क्या आजादी और जनतंत्र होने के बावजूद हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और नफरत की आंधियों में स्वाहा होते रहेंगे। मजहब और जातियों की दीवारों में कैद रहेंगे। हमें भगत सिंह के सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों जैसे राजगुरु और सुखदेव।

शहीद भगत सिंह और हमारे अन्य क्रांतिकारियों ने इस वतन के लिए वह अमिट छाप छोड़ तो दी। लेकिन वाकई जिंदा सच क्या है? कभी–कभी उनका नाम भी गाहे– बगाहे ले लिया जाता है लेकिन बार–बार लेकिन ही बनता रहेगा क्या? उनके सपने, सुझाए गए तमाम रास्ते अंधकार से भर दिए गए हैं। उनकी कुर्बानी को बिसरा दिया गया है। केवल लाई–लुप्प चल रही है। कितने आलेख याद कर रहा हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, बम का दर्शन। उनके पत्र और दस्तावेज जो हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं। इस दौर में महाझूठ ने सच को पाताल में गाड़ देने के पर्याप्त प्रयत्न किए हैं। वैसे सरकारें आती जाती हैं। सजती संवरती हैं लेकिन खुले आम जनता को तबाह करना, मूल्यों की हत्या इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हो रही है। हर संवेदनशील आदमी अफरा–तफरी का शिकार है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को उसके यथार्थ को मिथकों में बेहद करीने से बदला जा रहा है। और वह संघर्षपूर्ण विरासत इतिहास से ही दफन करने के प्रयत्न जारी हैं।

क्या–क्या वादे पतंग उड़ाओ महोत्सव की तरह समूचे आकाश मंडल में उड़ाए जा रहे हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हमारे जेहन में ताजा नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी एकयात्रा में उस स्थल को देखा है और वहां गोलियों के निशान भीऔर वह मौत का कुआं भी। लेकिन इन सभी बातों को गौर से देखा नहीं जा रहा है। उसे मात्र बहलाया और फुसलाया जा रहा है। इधर के वर्षों में इतिहास को कायदे से ढंका मूदा जा रहा है या लीपा पोती की जा रही है। पूरा देश प्रलोभनों के भंवरजाल में है। हमारी जिन्दगी भी प्रलोभन के जाल में है। युवाओं का जीवन हैं। जिसमें कोई नौकरी नहीं है। महंगाई की कोई चर्चा नहीं है। इस देश में किसान हैं लेकिन नहीं के बराबर। जो बार –बार लांक्षित और कलंकित किए जा रहे हैं। उनकी सक्षम आवाज तक को रौंद दिया गया है। उस पर दिन– रात बुल्डोजर चलाया जा रहा है। कितना कहा जा सकता है और कितना हम कह पा रहे हैं। समूचा जीवन हास्य, प्रपंच है प्रहसन हो गया लगता है।

पंजाब में शायद पहली बार अमर शहीद भगत सिंह के गांव में जाकर सरकार बनी है। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। हालांकि यह एक प्रतीक है फिर भी। लोगों को जोड़ने का एक जरिया तो आम आदमी पार्टी का है ही। इसके परिणाम बाद में देखे जा सकेंगे। क्रांतिकारियों की इच्छाओं को सपनों को साकार करने की एक छोटी सी कोशिश है यह। इसे मैं विधेय में देखता हूं। निर्णय तो भविष्य ही करेगा। वाह रे विकास देवता! शायद सड़कों का निर्माण और अन्य माध्यमों का निर्माण ही विकास माना जाएगा। चरित्र का, मूल्यों का क्षरण ही विकास होगा। उसमें परम प्रतापी भ्रष्टाचार की दुनिया सजी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की कोई जरूरत नहीं। तरह–तरह के मिसाइल छोड़ कर निशाना साधा जा रहा है। शहरों कस्बों और जीवन की वास्तविकता और हैसियत का नाम बदल देने से भी विकास होगा। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की अवज्ञा भी शायद विकास होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम भी खूबसूरती से उछाला जाता है। लेकिन हो उल्टा रहा है। क्रांतिकारियों और विवेकानंद जी के विचारों तक की निर्मम तरीके से हत्या का बेहिसाब कारोबार चल रहा है विशाल पैमाने पर। यह भी विकास का मॉडल है। कौन नहीं है निशाने पर। गांव –गांव बसें चलेंगी। धार्मिक यात्राओं की उड़ानें होंगी। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो सकती? भारतीय संस्कृति की दुहाइयों में छिपा आम आदमी का कोहराम होगा। जो नहीं होना चाहिए, वह होगा और जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। वह जरूर से जरूर होगा। स्वाधीनता आंदोलन किनारे लगा दिया गया है। पूर्व में अच्छे किए गए काम किनारे लगा दिए गए हैं। शायद यही हमारे देश का नए मॉडल का विकास होगा? नाटक चल रहा है। आगे भी जारी रहेगा। प्रश्न है कि क्या क्रांतिकारियों और शहीदों की स्मृति को नमन करने से ही हम अपने कर्तव्य की भूमिका निभाते रहेंगे या उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस और जीवन्त कार्रवाई करेंगे? इसे तय होना है।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां		
माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

इप्टा का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन...

पेज 16 से जारी...

बावजूद गीतो को सुनने के लिए शिवाजी मैदान में डटे रहे। नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार के अपने वादों और दायित्व से चूकने की आलोचना कर रही हैं, उन्हें इस काम के लिए इप्टा का समर्थन है।

सम्मेलन के दूसरे दिन प्रतिनिधि सत्र को संबोधित करते हुए भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य और राज्य सभा सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि देश बहुत ही खराब परिस्थिति में है। समाज में तेजी से फैलते नफरत के माहौल से बाहर निकालने के लिए इप्टा संस्कृति, कला, साहित्य और अन्य विधाओं में अपने व्यापक अनुभवों के आधार पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस काम के साथ–साथ अधिक से अधिक युवाओं को इप्टा के साथ जोड़ते हुए इप्टा को ऊर्जामयी बनाना होगा।

सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को उनकी रूचि के अनुसार, अलग–अलग सत्रों में विभाजित किया गया। उन सत्रों के अंतर्गत चली परिचर्चाओं और उनेक सुझावों को बाद में समस्त प्रतिनिधि सत्र में रखा गया। सम्मेलन में सामाजिक न्याय, आर्थिक असंतुलनता और सांप्रदायवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ वैज्ञानिक मनोवृत्ति, तार्किकता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। विज्ञान और तकनीक पर चले एक सत्र में नई विज्ञान और तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। सत्र में कहा गया कि सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतें जिस तरह से शोषित उत्पीड़ित जनता को गुमराह करने के लिए अंधविश्वास और मिथकों का सहारा ले रही हैं उससे निपटने के लिए हमें अपने नाटकों, कविताओं और पटकथाओं को नए सिरे से गढ़ना होगा। इस सत्र ने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच के विरोधाभासों को जनता को समझना होगा। जब हम सबूत को तर्कों के साथ किसी बात का जवाब देते हैं तो वह विज्ञान है लेकिन धर्म अंधविश्वास है। एक पंथ के लोगों के धार्मिक विश्वास से दूसरे पंथ के लोगों के धार्मिक विश्वास से अलग हैं लेकिन विज्ञान सार्वभौमिक है। एक अन्य सत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से किसानों, खेत मजदूरों, आदिवासियों के मुद्दों को उठाने पर चर्चा हुई।

प्रतिनिधियों के दूसरे और तीसरे सत्र में संगठनात्मक रिपोर्ट, प्रस्ताव और इप्टा की नई राष्ट्रीय कमेटी के लिए चुनाव हुए। इप्टा की नई राष्ट्रीय कमेटी में सचिवमंडल मंडल सहित 125 सदस्य हैं। इन सदस्यों में संरक्षक सदस्य शामिल नहीं है। इप्टा सम्मेलन ने महिला प्रतिनिधि प्रतिभागियों को अपनी कई कमेटियों का नेतृत्व सौंपा है। इप्टा के नए सचिवमंडल सदस्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ रंगमंच निर्देशक प्रसन्ना, राष्ट्रीय महासचिव तनवीर अख्तर, कार्यकारी अध्यक्ष राकेश वेदा, उपाध्यक्ष समिक बन्धोपाध्याय और कोषाध्यक्ष सुखेन्द्र मंडल हैं। सचिवमंडल के अलावा मीडिया, सोशल मीडिया और दस्तावेज कमेटियां भी बनाई गई हैं।

प्रतिनिधियों ने झारखंड इप्टा राज्य सचिव उपेन्द्र कुमार मिश्रा, कॉमरेड शैलेन्द्र के साथ–साथ स्वागत समिति के चेयरमैन डॉ. अरूण शुक्ला का गरमजोशी से मेजबानी की सराहना की।

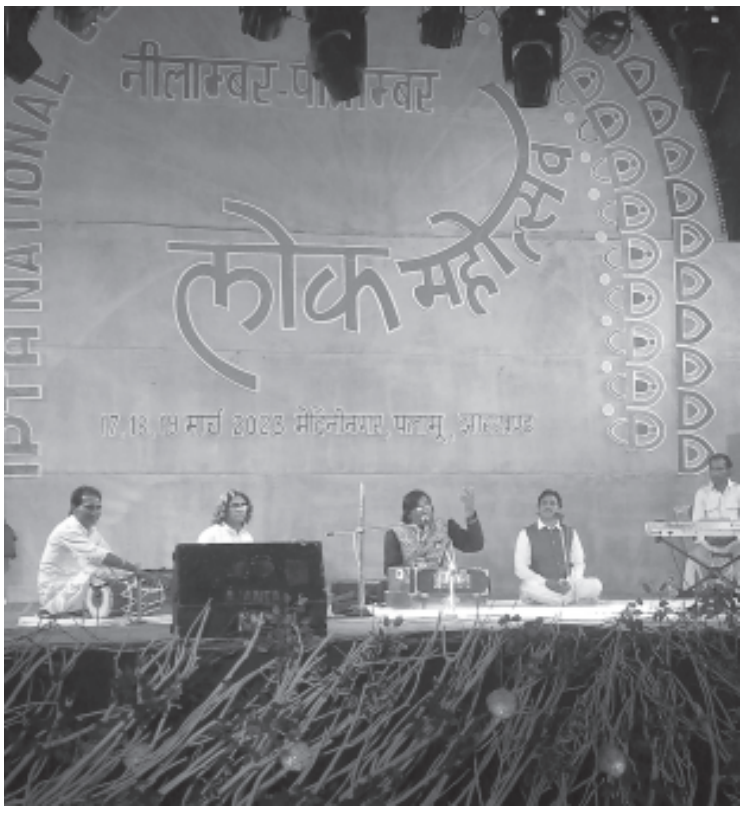

आइये, उनके आदर्शों के लिए काम करने ...

पेज 1 से जारी...

खो रहा है। 150 वर्ष से भी अधिक पुराना निवेश बैंक क्रेडिट सुईस दिवालियापन के कगार पर पहुंच रहा है। दुनिया में जीवन के अस्तित्व के संबंध में गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं और जैसा कि हम जानते हैं मौसम में बदलाव, भूमंडलीय वार्मिंग और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के मद्देनजर हमें इन चिंताओं को दूर करने की जरूरत है। शोषण की अमानवीय व्यवस्था सरकारों पर कब्जा करने, जनता में फूट डालने, टकराव और युद्ध पैदा करने समेत अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपने तमाम घिनौने हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। निर्दोष लोग तकलीफ उठा रहे हैं ताकि वह मौजूदा व्यवस्था चलती रही जिसमें चंद लोग समाज के सामाजिक श्रम को हड़प रहे हैं। यही चीज थी, यही पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए भगत सिंह उठ खड़े हुए और स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, संपन्नता एवं शांति के अपने प्रिय लक्ष्यों के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी। वह ''समूचे समाज का समाजवादी आधार पर पुनर्निर्माण करना चाहते थे''। वह पूरी तरह सही थे और हम जरा–सी भी शंका किए बगैर कह सकते हैं कि यदि मानवता को जिंदा रहना है तो लालच और फूटपरस्त आधारित व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर सहयोग एवं सौहार्द पर आधारित व्यवस्था को लाना होगा।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में, शहीद भगत सिंह देशभक्ति और बलिदान के एक प्रतीक के तौर पर एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वह इस देश के मजदूरों, किसानों, युवाओं एवं छात्रों के ध्येय के लिए शहीद हुए। आजकल प्रतिक्रियावाद, फूटपरस्ती एवं झगड़ा–फसाद की ताकतें उनकी छवि को तोड़–मरोड़ कर भगत सिंह की विरासत को हड़पने की कोशिश कर रही हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी चिंतक थे और धर्मनिरपेक्षता उनके खून में थी। हमें भगत सिंह के विचारों को जनता के बीच ले जाकर सुनिश्चित करना चाहिए कि हरेक भारतीय को जानना चाहिए कि उनकी शहादत का क्या मतलब है और किन आदर्शों के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। भगत सिंह के स्वयं के शब्दों में, ''पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी शोषण के दिन गिनती के हैं। यह संघर्ष न तो हमसे शुरू हुआ और न हमारे जीवन के बाद खत्म होने वाला है। यह ऐतिहासिक घटनाओं एवं वर्तमान हालात का अपरिहार्य परिणाम है''।

हमारा कर्तव्य है कि हम भगत सिंह के विचारों के अनुसार, अपने इर्द–गिर्द की दुनिया को समझें और उनकी विरासत को एक अंजाम तक पहुंचाएं, अर्थात ''लगातार संघर्ष, कष्ट एवं बलिदान के जीवन'' के जरिये हमारे देश में जनता का एक वास्तविक शासन स्थापित करें। आज हमारे चारों तरफ असमानता, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, पितृसत्तात्मकता और लड़ाई–झगड़े की बुराइयां बढ़ रही हैं। आवश्यकता है कि हम इनके खिलाफ संघर्ष करें, इन्हें पराजित करें और जनता के लिए विजय प्राप्त करें। अपने इस प्रिय लक्ष्य के लिए संघर्ष करना शहीद भगत सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

भाजपा (मोदी) भगाओ देश बचाओ पदयात्रा शुरू करेगी भाकपा

ग्वालियर, 20 मार्च 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्यप्रदेश राज्य कार्यकारिणी की बैठक 18–19 मार्च को प्रदेश मुख्यालय शाकिर भवन भोपाल में संपन्न हुई। जिसमें सभी कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्यप्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य कौशल शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बैठक में चर्चा उपरांत लिए गए निर्णय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 14 अप्रैल से 14 मई 2023 तक भाजपा (मोदी) हटाओ, देश बचाओ नारे के साथ पूरे देश में पदयात्रा करने जा रही है। इसी तारतम्य में ग्वालियर जिले में भी भाकपा पदयात्रा करेगी। एक माह की पूरी योजना ग्वालियर जिला परिषद की बैठक में अंतिम रूप से रूट तय किया जाएगा। इस वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है की विगत राज्य परिषद की बैठक में तय किये मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ा जाएगा, कुछ सीटों के नाम प्राथमिक रूप से तय किए गए जिनमें ग्वालियर, डबरा, कोतमा, अनूपपुर, बड़मारा, देवसर, चुरहट, गुड, भोपाल, इंदौर 2,गुना, राजपुर, सेंधवा शामिल हैं एवं अन्य स्थानों का भी चयन किया जायेगा। कौशल कौशल शर्मा ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आव्हान के अनुसार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और सरकार द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक नफरत के विभाजन की राजनीति के लिए खिलाफ तथा अदानी–मोदी के आर्थिक घोटालों की जांच पर जेपीसी की मांग के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर 1 माह तक पदयात्रा कर जनता के बीच में जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मेहनतकशो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देते हुए एक जन हितेषी लोकतांत्रिक सरकार के गठन की प्रक्रिया में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी, पार्टी की कोशिश होगी कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मतों का विभाजन रोका जावे और एक जनतांत्रिक तरीके से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में खड़े प्रतिनिधियों के हाथ में आए।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 26 मार्च – 1 अप्रैल, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 24.3.2023

नफरत की राजनीति के खिलाफ कलाकर्मियों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की मुहिम

इप्टा का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

सी. आदिकेशवन

नवीन ऊर्जा और क्रांतिकारी भावनाओं के साथ भारतीय जन नाट्य मंच (इप्टा) का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 17 मार्च से 19 मार्च 2023 को डालटनगंज के मेदिनीनगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव, एकता में विविधता और शांति कायम रखने के लिए जोर दिया।

सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि सच बोलना समय की जरूरत है ताकि देश के बहु–सांस्कृतिक ताने–बाने को बचाया जा सके और इसके लिए इप्टा सांस्कृतिक गतिविधियों को सघन करते हुए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी।

सम्मेलन ने कलाकर्मियों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि देश में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाए गए नफरत के मौजूदा माहौल के खिलाफ लड़ने के लिए एकता, बराबरी, शांति और बंधुत्व के संदेश को फैलाए।

तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान हर शाम शहर में जनगण के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार, पं.बंगाल, तेलंगाना, केरल से आए कला जत्थों ने अपने–अपने राज्य के नृत्यों और लोकनृत्यों को प्रस्तुत किया। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए शहर के कोने–कोने से लोग आए।

इप्टा सम्मेलन में 21 राज्य से 600 प्रतिनिधियों, वैकल्पिक प्रतिनिधियों, आमंत्रित प्रतिनिधियों एवं मेहमानों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने मृगेंद्र हाल में प्रतिनिधि सत्र के अलावा आयोजित परिचर्चा, सेमिनार, वर्कशॉप में हिस्सा लिया। शहर के टाउन हाल में इप्टा के सफरनामे से जुड़ी तस्वीरें, पोस्टर और अन्य सामग्री प्रदर्शित की गई थी।

17 मार्च 2023 को उद्घाटन दिवस पर देशभर से आए सांस्कृतिक कार्यकर्ता शिवाजी मैदान में एकत्रित हुए और वहां से डाल्टनगंज की सड़कों पर एक सांस्कृतिक जुलूस निकाला गया जो फिर से शिवाजी मैदान में वापिस पहुंचा और एक खुले मंच में तब्दील हो गया। इन मंचों को नीलांबर और पीतांबर लोक महोत्सव नाम दिया गया था। एकत्रित कलाकर्मियों और सांस्कृतिक रंगकर्मियों की रंग–बिरंगी पोशाकें वहां से निकलने वालों का ध्यान आकर्षिक कर रही थीं।

सांस्कृतिक जुलस की यात्रा के मार्ग पर स्थानीय संस्थानों जैसे कि अंजुमन इस्लाउल मुसलेमिन, इंडियन मानव अधिकार ऐसोसिएशन, खुल्लामंच और सामाजिक कार्यकर्ता पिंटु चौरसिया ने स्वागत मंच लगाए हुए थे जहां से वे कलाकर्मियों पर फूल बरसा रहे थे।

स्वागत मंच पर पानी, नाश्ता और शीतलपेय का इंतजाम किया गया था।

खुले सभा मंच पर श्रीलज बैनर्जी, गौहर रजा, डॉ. अरूण शुक्ला, सुखदेव सिंह सिरसा, टी. बालम, अमिताभ चक्रवर्ती, प्रेम भसीन और जानेमाने रंगकर्मी डॉ. प्रसन्ना मौजूद थे। प्रसन्ना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, ''ये नेता अब संस्कृति सीखा रहे है, ऐसे में सांस्कृतिक कर्मियों को देश के संकट और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में जनता को बताना चाहिए।''

गौहर रजा ने अपने संबोधन में कहा कि ''कला और संस्कृति के माध्यम से वैज्ञानिक समझ का प्रचार करना चाहिए ताकि बेसिर–पैर की बातों का खंडन किया जा सके'', नसीरूद्दीन ने घरेलू हिंसा और लैंगिक मामलों को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से उठाने की अपील की। मीनाक्षी पाहवा ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर जनगण को जागरूक करने की बात कही। सम्मेलन के दौरान चली परिचर्चाओं और सुझावों के आधार पर सम्मेलन को सुझाव दिया कि जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इप्टा को अपनी कला शैली तैयार करनी चाहिए।

सम्मेलन के आखिरी दिन खराब मौसम के बावजूद अपने गीतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जोरदार आलोचक नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुत किए। झमाझम बारिश के बीच उन्होंने अपना गायन जारी रखा और जनगण भी भारी बारिश के

शेष पेज 15 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.